साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 अंक 17 प्रति सोमवार इंदौर, 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

भारत में 140 करोड़ मोबाइल सभी साइबर अपराधियों के निशाने पर

बेहतर हो ऑनलाइन लेनदेन बैंकिंग करें तुरंत बंद

5जी के आने के बाद देश विश्व में साइबर अपराधों में 5वां, सरकार के भरोसे ना रहे आपकी सुरक्षा आपके हाथ... साइबर अपराधों पर जनता की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय अध्ययन

भारत के साइबर क्राइम खतरे के परिदृश्य ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है. देश 2023 की पहली छमाही में वैश्विक मैलवेयर और ऑनलाइन बैंकिंग मैलवेयर का पता लगाने में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है. ट्रेंड माइक्रो की मध्य-वर्ष साइबर सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार, भारत मैलवेयर का पता लगाने में दुनिया के शीर्ष पांच देशों में से एक है, जो पहले छह महीनों में कुल 90,945 रैंसमवेयर का पता लगाने में से 5.5 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है.

मैलवेयर हमलों के मामले में भारत चौथे स्थान पर- भारत ऑनलाइन बैंकिंग मैलवेयर हमलों में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, जो वर्ल्ड पापुलेशन के हिसाब से लगभग 8.2 प्रतिशत है. साल 2023 के दौरान शुरुआती महीनों में महत्वपूर्ण 5609 ऑनलाइन मैलवेयर हमलों की पहचान की गई. इन खतरों का असर विभिन्न क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है.

सरकारी क्षेत्र को 18862 मैलवेयर हमलों का सामना करना पड़ा. जबकि, बैंकिंग क्षेत्र को 15,514 मैलवेयर हमलों का सामना करना पड़ा. विशेष रूप से कोमिनेर, मिमिकेट्स और पावलोड जैसे मैलवेयर समूह विनिर्माण, सरकार और बैंकिंग उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करते हैं.

साइबर अपराध तेजी से बढ़ें- भारत साइबर सुरक्षा दुविधा का सामना कर रहा है इसलिए, डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता सर्वोपरि है. साइबर अपराधी तेजी से परिष्कृत होते जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बना रहे हैं. वैश्विक स्तर पर, चालू वर्ष की पहली छमाही में 85 अरब खतरों को अवरुद्ध किया गया, जिसमें 37 अरब ईमेल धमकियां और 46 अरब दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलें शामिल हैं. वैश्विक स्तर पर बैंकिंग, खुदरा और परिवहन शीर्ष तीन उद्योग हैं, जिनमें 52 सबसे अधिक रैंसमवेयर हमले हुए हैं, जिनमें साइबर हमले भी तेज़ी से बढ़ें है.

साइबर क्राइम क्या है?

साइबर अपराध कोई भी आपराधिक गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क शामिल होता है। जबकि अधिकांश साइबर अपराध साइबर अपराधियों के लिए लाभ उत्पन्न करने के लिए किए जाते हैं, कुछ साइबर अपराध सीधे कंप्यूटर या उपकरणों के खिलाफ उन्हें नुकसान पहुंचाने या अक्षम करने के लिए किए जाते हैं। अन्य लोग मैलवेयर, अवैध जानकारी, चित्र या अन्य सामग्री फैलाने के लिए कंप्यूटर या नेटवर्क का उपयोग करते हैं। कुछ साइबर अपराध दोनों ही करते हैं - यानी, कंप्यूटर को कंप्यूटर वायरस से संक्रमित करने के लिए लक्षित करते हैं, जो बाद में अन्य मशीनों और, कभी-कभी, पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। साइबर अपराध का प्राथमिक प्रभाव वित्तीय है। साइबर अपराध में कई अलग-अलग प्रकार की लाभ-संचालित आपराधिक गतिविधियां शामिल हो सकती हैं, जिनमें रैंसमवेयर हमले, ईमेल और इंटरनेट धोखाधड़ी, और पहचान धोखाधड़ी, साथ ही वित्तीय खाते, क्रेडिट कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड की जानकारी चुराने का प्रयास शामिल है। **(शेष पेज 6-7 पर)**

हेलमेट पर जालसाजी पूर्ण वसूली के लिए सख्ती क्यों?

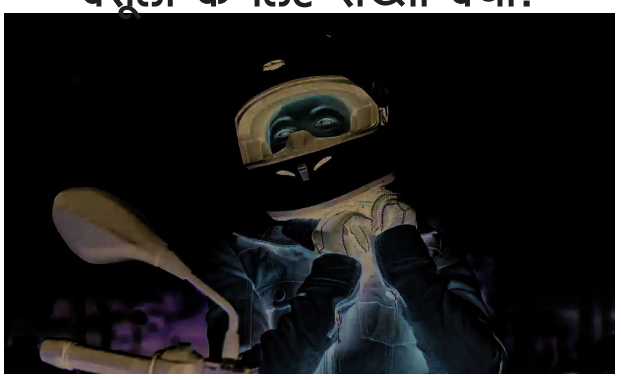

पुलिस यातायात सुधारे हेलमेट की नौटंकी करे बंद

वाहन चालकों को भी अपने शरीर की सुरक्षा की चिंता... कैमरों से यातायात सुधारने, नियंत्रण का अध्ययन अपराधियों की पकड़ भी करना चाहिए

हेलमेट खासतौर से पुलिस यातायात सुधारने की अपेक्षा चौराहा पर हेलमेट पहनाने के लिए जबरदस्ती करती है। बेशक हेलमेट से सुरक्षा होती है परंतु विवश करके अपना माल बेचने मोटी कमाई करने और उसके नाम पर दो पहिया चालकों को डराने धमकाने और वसूली करने का शरण से कर रही है यह पूर्णत असंवैधानिक है। हेलमेट से सुरक्षा होती है यह चालक जानता है और उसकी अपनी चिंता है वह भी चाहता है सड़क पर चलते समय सुरक्षित रहे दुर्घटना कभी भी किसी भी क्षण हो सकती है। पर हेलमेट से जो परेशानी होती है वह सरकार नहीं जानती। सरकार को गर्मियों में हेलमेट पहनने से सिर में भारी पसीना आने व बहने, के साथ माथे पर सिर में बालों में खुजली होने लगती है और जो भी चालक बालों को काला करने के लिए काले रंग का प्रयोग करते हैं उनको खुजली मचने, होने के साथ फोड़े फुंसियों तक बाहर आ जाते हैं। जो जिसके कारण हेलमेट लगाना अत्यधिक कष्टप्रद सिद्ध होता है।

(शेष पेज 7 पर)

चीन व अमेरिका विश्व को बांट रहे घातक बीमारियों - भाग 1

वस्त्र, परिधान, औषधियां, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, खिलौने स्वास्थ्य के लिए घातक

विश्व के अनेकों देशों की कृषि स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निष्कर्ष

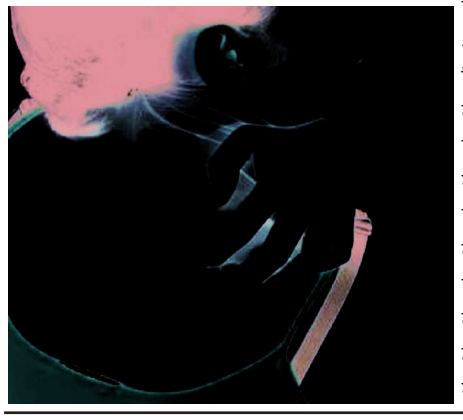

अमेरिका व चीन विश्व में जो अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्मार्ट वॉच मोबाइल मोबाइल टावर से घातक रेडियो एक्टिव तरंगों से, कृषि में घातक कीटनाशक जो यूरोपियन देशों में प्रतिबंधित हैं, खिलौने, पटाखे पतंग के धागे, खाद्य वस्तुएं, औषधियां, घातक कृत्रिम तत्वों, रंगों से निर्मित वस्त्र आदि जो मानव शरीर को त्वचा रोगों से फिर लेकर नपुंसकता, हृदय, यकृत, प्लीहा, गुर्दों, आंखों को कमजोर करने, की बीमारियों के साथ इन सब शरीर के अंगों को निस्तेज करने से मृत्यु तक व आबुर्द, क्षय, अस्थमा, जैसी दीर्घकालीन बीमारियां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अपनी घातक महंगी दवाइयां उपकरण टीके आदि बेंचने का षड्यंत्र कर मोटी कमाई कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम पुनः भारत के पुरातन आयुर्वेद की तरफ प्रकृति के साथ मिलकर प्राकृतिक तरीके से इन सब का बहिष्कार कर सुखद और स्वास्थ्य जीवन जीने का प्रयास करें। वस्त्रों की घातकता के कुछ महत्वपूर्ण विश्व के अनेक देशों की प्रयोगशालाओं के निष्कर्ष प्रस्तुत है।

भारत में 2014 में विनाश पुरुष मोदी के सत्ता संभालने के बाद चीन अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनियों, शॉपिंग मॉल से मोटा पैसा लेकर देश में 2014-15 में पहले सफाई के नाम लगभग 10 करोड़ से ज्यादा ठेले, पग मार्गों पर घरेलू उत्पादों की सामग्री बेचने वालों को साफ किया। जनता का डाटा इकट्ठा करने उनकी लेन देन की प्रक्रिया, जनता के कमाई, उपभोग के तरीके, स्तर, मात्रा, आवश्यकता जानने, मनचाही वसूली के लिए कैशलेस का षड्यंत्र किया। इसके लिए उसने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा कर लोगों को कैशलेस लेनदेन करने के साथ लगभग देश के 20 करोड़ से ज्यादा उद्योग धंधों व्यापार व्यवसायों को नगदी के अभाव में बंद कर चौपट कर दिया। ताकि चीन व अमेरिकी कंपनियों का माल आसानी से मनमानी कीमतों पर बिक सके। उसके बाद जीएसटी और कोरोना ने भी देश के उद्योग व्यवसाय धन्धों को चौपट कर दिया और उसका फायदा अमेरिका चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों उद्योगों को मिला।

चीन से खरीदे गए कपड़े कितने सुरक्षित हैं? एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से आयातित कपड़ों में जहरीले रसायनों का अस्वीकार्य स्तर होता है।

कपड़ों पर रसायनों के अवशेष मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। वैश्विक जागरूकता के बारे में बढ़ती चिंता ने उपभोक्ताओं में जैविक कपड़ों की इच्छा जगा दी है, जिससे अधिक से अधिक लोग प्रकृति की जीवन शैली चुनने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। बच्चों के कपड़ों की खरीदारी में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वे गैर-विषैले, पर्यावरण के अनुकूल और रसायनों और त्वचा की जलन से मुक्त होने चाहिए। एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला तथ्य बताया गया है कि चीन से आयातित कपड़ों में अत्यधिक रासायनिक सामग्री होती है जो बच्चों के साथ सभी को नुकसान पहुंचा रही है।

(शेष पढ़ें अगले अंक में)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

सत्ताधीशों के पाप भी पुण्य, विपक्ष के पुण्य भी पाप

सच मत बोल मुंह मत खोल अन्यथा हम सत्ताधीश हैं इसमें बचाने का देखा हमारा रोल

भारत में जाहिल, चांडाल मोदी के सत्ता में आने के बाद, देश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई। अपराध, बलात्कार, सांप्रदायिक जातिगत दंगे, बलवे आगजनी, आतंकवाद, पत्रकारों पर हमले, सत्ता के इशारे पर नाचने, सत्ताधीशों के भ्रष्टाचार लूट खसोंट अपराध बलात्कार छुपाने, जनता को लूटने, देश, देश की संपत्तियों को बेंचने, भुखमरी, बेरोजगारी बर्बादी को छुपा जनता को भ्रमित करने के लिए प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता खत्म कर छल, बल, दल से अपनी झूठी प्रशंसा करवाने की भांड व भड़वा गिरी सब बढ़ी। जिसने जनता की पीड़ा को बढ़ाया। उसका सच बोलने वालों को उल्टे सीधे जबरदस्ती के कानून थोप कारागृहों में डाला गया, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर सीबीआइ, ईडी व अन्य जांच, सुरक्षा एजेंसियों को सत्ता रूढ़ दल के नेताओं मंत्रियों के हवाला, करो की चोरी, भ्रष्टाचार लूट, डकैती, बलात्कार, जुयें, सट्टे, अवैध कब्जों, खनन, बिजली चोरी, शराब ड्रग्स आदि के वास्तविक अपराध रोकने की अपेक्षा उनसे मोटी कमाई की व्यवस्था की गई। वही अवैध काला धन हाल ही में हुए चुनावों में पानी से ज्यादा तेज गति से बहाकर भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों व सीमा से हजारों गुना ज्यादा खर्च किया गया। विधायकों के चुनाव लड़ने वह अपने प्रचार प्रसार की खर्च की सीमा रुपए 35 लाख होती है के विपरीत एक अरब रुपए तक खर्च किया गया जबकि उम्मीदवारों को अपने राजनीतिक दलों से खासतौर पर भाजपा के उम्मीदवारों को प्राप्त अपशिष्ट खबरों के अनुसार 50 से 100 करोड रुपए भी चुकाना पड़ा इसके बाद में भी मतदाताओं को खरीदने भ्रमित करने वोट डालने या न डालने के लिए मनाने में, अपने पक्ष में वोटिंग करवाने में पायजेब-साड़ी-मोबाइल-टीवी-भोजन भंडारे, हजारों रुपए की टिप्स में भी अरबो रुपए खर्च किया गया तो आखिर इतना पैसा आया कहां से और चुनाव आयोग व उसके प्रतिनिधि अधिकारियों की आंख के सामने खर्च किया गया। तो इतना पैसा आया कहां से? इसकी जांच क्यों नहीं की जाती या जिन सत्ताधीश नेताओं ने यह धन खर्च कर चुनाव आयोग की सीमाओं का खुला मजाक उड़ाया। पर वो सत्ताधीश नेताओं के लिए देश का कोई कानून नहीं। उल्टे ही जिन्होंने इस पर आवाज उठाई, भ्रष्टाचार लूट खसौट बलात्कार माफिया के खिलाफ जो बोले उसने अनेकों प्रकार से इसकी सजा पाई। दूसरी तरफ घोर धूर्त मोदी ने सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद राहुल गांधी को पनौती बताया, उल्टे-सीधे आरोप लगाए निम्न भाषा का प्रयोग कियापर उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी और वही जब भाषा का प्रयोग राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल व अन्य विपक्षी दलों ने किया तो उनको डराने धमकाने उनकी संपत्तियां जप्त करने ईडी के छापे मारने आदि का कार्य किया जा रहा है। 6 महीने से मिजोरम सांप्रदायिक व जातिगत दंगों की आग में जल रहा है। उस पर सत्ताधीशों ने कोई आवाज नहीं उठाई। शांत करने का प्रयास नहीं किया गया। ना ही तेजस में बैठकर, देश विदेश की यात्रा करने क्रिकेट मैच देखने जाने की फुर्सत है। पर अपनी ही जालसाजियो कुकर्मों से मिजोरम में दंगा भड़काया गया जो पिछले 6 महीने से अनवरतचल रहा है कभी प्रधानमंत्री या अन्य सभी मंत्रियों कोवहां जाने की फुर्सत या निर्देश नहीं मिले। और विपक्षी नगर इन सब पर उंगली उठाई तो वह देशद्रोही अपराधी और पापी हो गया। पर जुए सट्टे बलात्कार भू कॉलोनी ड्रग माफिया जैसे कामों को सत्तारूढ़ दल के मंत्री ब्रजभूषण करें। तो ऐसी राक्षस बलात्कारी पुण्यात्माओं को बचाने, आंदोलनकारियों को कुचलने, दुष्प्रचार कर अपराधियों को बचाने, कानून को कमजोर करने जांच और सुरक्षा एजेंसी को जांच न करने देने के हर हर्षवर्धन मोदी गृहमंत्री अमित शाह तक ने उसको बचाया क्योंकि वे सब पुण्य आत्मा थे। बाकी विपक्ष पुण्य कार्य करें, उनकी आवाज़ उठाएं, बेरोजगारी, भुखमरी, अपराधों के विरुद्ध आवाज़ उठाएं तो वे सब पापी हैं और जांच के दायरे में है। उल्टे ही उन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई जाती, फरियादी अगर रिपोर्ट लिखवाने पहुंच जाए तो पुलिस ऐसे और संजय अपराधों के मामले में भी शांत रहती है। कोर्ट में कैस लगाने पर न्यायाधीशों को डराया धमका बचाने का प्रयास जाता है। तो आखिर यह तांडव, कानूनों का मजाक, कब तक, क्यों, कैसे?

विधानसभा चुनाव 2023 में ही दो दलों ने किए खर्चे

मप्र में रू. 20000 करोड़ के काले धन का विधानसभा चुनाव

230 सीटों पर 460 प्रमुख उम्मीदवारों को खर्च करना पड़े करोड़ों, कई सीटों पर तो 50 से 100 करोड़ तक खर्च कर देने की भी जानकारी आई सामने

लोकतंत्र को चुनावों में धन खर्च करने के कारण लूट तंत्र बना दिया। क्योंकि जब तक नेता लूटेगा नहीं, तो चुनाव जीतनेधन कहां से खर्च करेगा और जो पहली बार लड़ रहे हैं? तो भी सत्ता रूढ़ दल में टिकट की कीमत ही 50 से 100 करोड रुपए हो चुकी है। दूसरी तरफ विपक्ष में सत्ता से बाहर रहने के कारण धन न होने के बाद में भी 5 से 10 करोड रुपए केवल टिकट खरीदने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं तक को देने वा खर्च करना पड़ते हैं। जबकि विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को लुभाने के लिए उम्मीदवार जो लगभग हर दल में 200 से ज्यादा हैं। काली कमाई से कमाया है? दोनों दलों के उम्मीदवार औसतन ड्रग भू कॉलोनी शिक्षा सेक्स शराब सप्लाई, रेत, खनन, मिलावट, ठेका चोरी डकैती जालसाजी आदि के माफिया हैं और अपने कारोबार को बचाने ही राजनीतिक दलों में घुसकर काले धन से ही टिकट खरीद चुनाव लड़ते हैं।

चुनाव आयोग लाख मतदाताओं को ना खरीदने से लेकर चुनावी खर्च पर अंकुश के दावे करता रहा हो, मगर हर चुनाव में तय की गई सीमा से सैकड़ों गुना अधिक राशि खर्च की जाती है, जो एक सामान्य मतदाता को भी साफ-साफ नजर आता है। इस बार का विधानसभा चुनाव अब तक का सबसे महंगा साबित हुआ, जिसमें उम्मीदवारों के साथ-साथ दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा ने पानी की तरह करोड़ों रुपए सत्ता हासिल करने के लिए बहा दिए। एक मोटे अनुमान के मुताबिक 3 हजार करोड़ से ज्यादा का कालाधन इंदौर सहित प्रदेश की सभी 230 सीटों पर बहाया गया है। इन सीटों पर दोनों प्रमुख दलों के कुल उम्मीदवार 460 होते हैं और एक उम्मीदवार का चुनावी खर्च 50 से 100 करोड़ रुपए भी औसत माना जाए तो 23000 करोड़ रुपए का आंकड़ा आता है, जबकि कई सीटें ऐसी

रहीं, जिन पर उम्मीदवारों को 25-50 करोड़ से लेकर 50-100 करोड़ तक खर्च करना पड़े। जैसे इंदौर में विधानसभा एक का चुनाव सबसे खर्चीला साबित हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने हेलीकॉप्टरों, चुनावी रैलियों, रोड शो, स्टार प्रचारकों सहित अन्य प्रचार-प्रसार, मीडिया पर भी करोड़ों रुपए की राशि खर्च की और यह पूरा पैसा दो नम्बर का यानि कालाधन ही रहा।

जब भी चुनाव आते हैं तो बाजार में जमा कालाधन भी बाहर आ जाता है, जिससे कई वर्ग को अच्छा कामकाज भी मिल जाता है। अब वे दिन गए जब सेंव-परमल खाकर कार्यकर्ता काम करता था। अब सारे कार्यकर्ताओं को गाडियों के साथ-साथ पेट्रोल-डीजल तो लगता ही है, वहीं दोनों वक्त चाय-नाश्ता, भोजन के साथ नकद राशि भी उम्मीदवारों को देना पड़ती है। इसके अलावा समाज के ठेकेदारों के साथ-साथ निर्दलीय, बागी या अन्य असंतुष्टों को मनाने पर भी लाखों खर्च हो जाते हैं। चुनाव आयोग ने भले ही एक उम्मीदवार के लिए 40 लाख रुपए की सीमा खर्च की तय की हो और सारे उम्मीदवार आयोग की आंखों में धूल झोंकते हुए इससे कई गुना अधिक राशि नए-नए तरीकों को इजाद कर खर्च कर देते हैं और अपना चुनावी खर्च 40 लाख तो छोड़ 10-20 लाख भी नहीं बताते। अभी भी इंदौर के जिन उम्मीदवारों ने चुनावी खर्च का ब्योरा दिया है, उसे देखकर ही अंदाजा लग जाएगा कि किसी एक ने भी 35-40 लाख रुपए खर्च होना नहीं बताए हैं, जबकि यह सभी को पता है कि एक उम्मीदवार का चुनाव भी कम से कम 40 से 50 करोड़ खर्च करना मामूली बात है।

हालांकि एक बड़ी राशि चुनावी चंदे के रूप में उगाही जाती है, वहीं कई सक्षम उम्मीदवारों को अपनी जेब भी ढीली करना पड़ती है। चुनाव प्रचार-प्रसार अत्यंत महंगा हो गया है, वहीं मीडिया का भी खर्च बढ़ गया है, क्योंकि अखबारों के साथ-साथ ढेर सारे न्यूज चैनल, पोर्टल सहित सोशल मीडिया भी शामिल है। यहां तक कि अधिकांश उम्मीदवारों ने अपनी खुद की आईटी सेल और मैनेजमेंट टीम बनाकर भी प्रचार-प्रसार पर मोटी राशि खर्च की, वहीं हेलीकॉप्टर भी खूब उड़े और चुनावी रथ तो दौड़े ही। विज्ञापनों, होर्डिंग पर भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। यह अब तक का सबसे महंगा चुनाव मध्यप्रदेश में लड़ा गया।

विश्व एडस दिवस का सच, कंडोम बेचने का षड़यंत्र

पेज 8 का शेष

निसंदेह कंडोम ऐसे सभी यौन रोगों और अनावश्यक स्त्रियों में गर्भ को रोकता है। जिसे 1998 से लगातार बार-बार मेरे समय माया द्वारा प्रकाशित करने के कारण जो कि अमेरिका के व्हाइट हाउस, व अन्य देशों के दूतावासों को डब्ल्यूएचओ को भी पीडीएफ कॉपी भेजी जाती है। जानबूझकर उन्होंने एड्स के प्रचार की अपेक्षा अस्पतालों में भी यौन रोग और गर्भनिरोधक के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसके संबंध में भोपाल के ज़ी टीवी कंपलेक्स में सन 1960 से लेकर 2008 तक चलने वाली ब्रिटिश लाइब्रेरी में 98 के अंत में लंदन टाइम्स में नार्वे के 200 डॉक्टरों के एक समूह ने इस पर काफी शोध करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला की यथार्थ में एड्स नाम की कोई बीमारी नहीं होती। वह केवल कंडोम बेचने और उससे अरबों रुपए प्रतिदिन की कमाई करने का षडयंत्र मात्र है। एड्स के भय को फैलाने और कंडोम से मोटी कमाई करने में एशियाई देशों में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए वर्ल्ड हजार्डियस आर्गेनाइजेशन ने हीं इस प्रपंच का षड्यंत्र रुचकर एड्स नाम की काल्पनिक बीमारी को पैदा कर यह भय 1980 से सभी प्रसार माध्यमों पर फैलाना शुरू कर दिया था। वैसे इस षड्यंत्र के पीछे विश्व शैतान संघ का छिपा षडयंत्र यह भी था कि एशियाई देशों में पारिवारिक संबंधों और मूल्यों को खत्म कर यौनाचार की उच्च श्रृंखलता फैला कर आसानी से हिंदू धर्म को नष्ट किया जाए और ईसाइयत को बढ़ावा दिया जाए। इसमें वे पूर्णतया सफल रहे हिंदू धर्म के पारिवारिक मूल्यों को नष्ट कर उच्च श्रृंखलता को बढ़ाने में वे सफल रहे।

मेरे पाठकों को अब समझ में आ गया होगा कि एड्स नाम की बीमारी क्या है?

सत्ताधीशों के इशारे पर गिनती में जालसाजी हर कदम पर

कलेक्टर व पूरा प्रशासन गिनती में भी करता है भारी जालसाजी

हर कमरे में लगी हर मशीन की हर उम्मीदवार को मिले वोट की, फिर हर चक्र की हर मशीन की एक्सेल शीट के बाद, सभी कक्षों की हर चक्र की, अंत में, सभी कक्षों के सभी चक्रों की सकल महायोग की एक्सेल शीट कभी नहीं बनाई गई न की जाती।

हर उम्मीदवार को हर मशीन की, कक्ष के, हर चक्र के योग की, हर कक्ष के हर चक्र के महायोग की, और अंत में हर मशीन के हर चक्र हर कक्ष के हर चक्र की एक्सेल शीट सभी कक्षों के हर चक्र के महायोग की एक्सेल शीट व अंत में, सभी कक्षों के सभी चक्रों की सकल महायोग की

एक्सेल शीट की प्रमाणित प्रति लेनी व ईमानदारी से निर्वाचन अधिकारी को हर उम्मीदवार को देना चाहिए।

जो की रिकॉर्ड में रखी जाना चाहिए और जिसमें कम से कम 12 से 15 घंटे लगते हैं। केवल एक विधानसभा में, क्योंकि इतनी मशक्कत करने से ज्यादा जरूरी होता है, की जालसाजी पूर्ण तरीके से मन से हीएक कक्ष मेंअलग अधिकारी बैठकर एक्सेल शीट बना चिल्ला कर मनपसंद या सत्ताधीश के उम्मीदवार को जीतना बता देते हैं। जो पूर्ण जालसाजी होती है।

जो शुरुआत में कलेक्ट्रेट कार्यालयो में कलेक्टर सभी उम्मीदवारों को बुलाकर बैठाकर यह सारी कहानी समझाता जरूर है। की सारी मशीन कंप्यूटर से जुड़ी हुई है हर मशीन का रिजल्ट कंप्यूटर में जाएगा और कंप्यूटर हर कक्ष की हर चक्र की, फिर सभी कक्षों की हर चक्र की व अंत में सभी कक्षों की सभी चक्रों की एक्सेल शीट बनाएगा पर कभी यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती और जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा ले जाते हैं। उनके पास कोई शीट नहीं पहुंचती। वह सारे दिन खाली घूमते रहते हैं। क्योंकि उनके पास शीट नहीं पहुंचाई जाती और मेरा सच अगर गलत है तो सभी चुनावों की, सभी मशीनों की, हर चक्र की, हर कक्ष की सभी चक्रों के योग की, सभी कक्षों के, सभी चक्रों की महायोग की, सभी मशीनों के सभी कक्षों की, सभी चक्रों के सभी कक्षों की अलग-अलग योग, महायोग, सकल महायोग की एक्सेल शीट प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवा देंवें। इसके आधार पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के रूप में बैठे हर जिले के जिलाधीशों को जालसाजी पूर्ण तरीके से घोषित चुनाव परिणामों के लिये निलंबित व सेवामुक्त किया जा सकता है।

चुनाव में वोटो की गिनती में भी हर जिले में हर कदम पर भारी जालसाजी की जाती है। और विपक्ष के हर उम्मीदवार को हर मशीन पर अपने आदमी बैठा कर सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जहां की मशीन खुली जा रही है वहां पर वही मशीन खुली जा रही है जिस पर उनके प्रतिनिधि ने उसे मशीन के कोड नंबर के साथ उस मशीन को बंद करते समय की लगाई सील पर उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर है। या नहीं यह देखा जाना चाहिए।

अगर उसे मशीन पर मतदान केंद्र पर उपयोग की गई मशीन का कोड नंबर व वहां बैठे प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं है तो वह मशीन बदली गई है। या उसका टेग व सील व हस्ताक्षर वाली पर्ची उखाड़ कर नई बदल कर रखी गई मशीन पर लगा दिया गया है। यदि उस इवीएम मशीन का कोड इलेक्ट्रॉनिक कोड नंबर व उम्मीदवार के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं मिलते हैं। तो मशीन बदल दी गई है और उसे पर तत्काल अपना विरोध जीत कर उसे मशीन का पंचनामा बनवाकर उसे मशीन को हटवाने की मांग की जाए।

यदि मशीन का मतदान केंद्र वाला कोड नंबर और वहां बैठे प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर सही पाए जाते हैं तभी ही उसे मशीन को खोलने की स्वीकृति दी जानी चाहिए प्रतिनिधियों द्वारा और उसका टेक को संभाल के रखा जाना चाहिए उसका कोड नंबर भी संभाल कर रखा जाना चाहिए और मशीन में गिनती बताने वाले के साथ तत्काल जो मटन की संख्या निकली है उसकी गिनती की तत्काल हर मशीन के सामने बैठा प्रतिनिधि मोबाइल से फोटो ले और उसकी सत्यापित प्रति की मांग करें। वही सत्यापित प्रति उसे कक्षा में बैठी सभी मशीनों के जो उसका हर राउंड का कक्ष में रखें सभी मशीनों के डाटा को डाटा एंट्री ऑपरेटर ने सही ढंग से डालकर हर चक्र की योग की फोटोकॉपी भी लिकर उसको एक व्यक्ति अलग से सत्यापित करता रहे और उसके योग को भी सत्यापित करें अब इसमें मान लीजिए हर राउंड में 10 उम्मीदवारों को एक 10 मशीनों का डाटा अर्थात सो प्रविष्टियां एक्सेल शीट में सही ढंग से की गई है या नहीं उसकी जांच और जचने के बाद उन सब का योग जांचें, योग में या हर मशीन की डाटा एंट्री में त्रुटियां जो गलत है उसके ऊपर आपत्ति

उठाएं। सही पाए जाने पर हर विधानसभा के कुल यदि 500 मशीनों की गिनती के लिए यदि 10 कक्ष बनाए गए हैं तो हर कक्षा की एक्सेल शीट को लेकर उनका हर चक्र का कुल महायोग बनाएं, हर एंट्री से के सत्यापन की पुष्टि करें और त्रुटियों को देखें गलत डाटा एंट्री पर आपत्ती लेने योग सुधरे और इस प्रकार से यदि 500 मशीनों की पहले राउंड में पांच कक्षा में 10-10 की एंट्री हुई है तो 5 कक्षा में 100 मशीनों का कल महायोग देखें और सत्यापित करें उसकी सत्यापित फोटो कॉपी प्राप्त करें पांच राउंड में अगर 500 मशीन खोली गई है तो हर राउंड का हर कक्षा का हर कक्षा के बाद में सभी कक्षाओं का हर राउंड का योग देखें और अंत में पांच राउंड की 500 मशीनों का कुल योग सत्यापित कर पुष्टि करें और उसकी सत्यापित फोटोकॉपी लेवें।

मैंने दो लोकसभा के और इंदौर में एक महापौर का चुनाव लड़ा है। यह हरामखोर जालसाजी कलेक्टर बोलना तो है। समझाता भी है परंतु आपको बता दूं कि सभी कक्षाओं के किसी भी राउंड की हर कक्षा की कुल मशीनों की गिनती की एक्सैल सीट नहीं बनाई जाती। हर राउंड की एक्सेल शीट नहीं बनाई जाती तो स्वाभाविक है कक्षा की योग की फिर हर राउंड की हर कब्ज के योग की कुल योग की कल महायोग की और कल अंत में शक्ल महायोग की एक्सेल शीट ही कभी नहीं बनती यह हरामखोर जालसाज आज एडीएम-एसडीएम स्तर के अधिकारी मन से ही दिन से जितना ज्यादा धन मिला है और सट्टा का जितना ज्यादा दुरुपयोग किया है उनके पक्ष में ही घोषणाएं करते रहते हैं।

दिशा कलेक्टर आपको कहानी जरूर समझाएगा पर यह सूअर के पिल्ले जलसा हरामखोर कितनी जलसा दिया करते हैं मुझे मालूम है मैंने अपनी आंखों से देखा देखा है जब सेट मांगी गई तो ना तो उन्होंने मशीनों को सीट दी ना हरकत के हर राउंड की सिद्धि ना हर राउंड की सारी कक्षाओं की सीट दी ना इन्होंने महायोग निकला न कुछ किया और जिस काम को करने में लगभग 12 से 14 घंटे लगने चाहिए यह हरामखोर 2 से 3 घंटे में ही सबकी घोषणा कर देते हैं। तो जितने भी उम्मीदवार हैं उनको देखना चाहिए की हर कक्ष में होने वाली जालसाजियों हर मशीन के सत्यापित सीट को पढ़ने फिर हर चक्र के हर कक्ष के एक्सेल शीट फिर हर चक्र की सभी कक्षों की जितने भी चक्र गिनती की जा रही है उन सब की सकल योग की गिनती और उसके बाद में अंत में सकल महा कुल योग की वर्गीकृत तालिकाओं के साथ हर सीट की कापी हर उम्मीदवार को पाने का हक है।

जो कभी नहीं दिया जाता। कभी नहीं किया जाता और मन से ही यह हरामखोर घोषणाएं करते रहते हैं और मेरा सच इन कड़वे शब्दों में इसीलिए व्यक्त की जा रही है क्योकि मैं पीड़ित और भुक्त भोगी हूं मैंने तीन चुनाव लड़े देख समझा और सबकी प्रतियां मांगी इन हरामखोर जालसाजों ने कभी हर मशीन की सीट हर कक्ष की एक्सेल हर राउंड की और सकल योग की सीट मांगने पर कभी नहीं दी और यह वर्गा लाते रहते हैं। क्योंकि यह बनाते ही नहीं और तीनों चुनाव में ना कभी हर कक्ष के हर चक्र की हर उम्मीदवारों कुल योग की एक्सेल शीट बनाई जाती है ना योग बताया जाता है ना दी जाती है उसके बाद में सभी कक्षों की हर चक्र की सीट का भी डाटा कभी एक्सेल शीट में ना तो भरा गया ना बताया गया ना उसकी फोटो कॉपी दी गई यही हाल फिर हर कक्षा हर चक्र का सकल महायोग की सीट बनाई गई और नई उसकी फोटोकॉपी दी गई और मेरी बात अगर झूठ है और यह रिकॉर्ड इनको बनाना चाहिए था अगर है तो यह हरामखोर 8 साल बाद तो क्या तीन दिन बाद भी नहीं दे पाते तो 8-10 साल बाद क्या दे पाएंगे? क्योंकि बनाई ही नहीं जाती और मन से ही घोषणा करके फैसला कर दिया जाता है जो सबसे ज्यादा काम उम्मीदवारों से कलेक्टर, निगम कमिश्नर, एडीएम, एसडीएम के साथ करते हैं उनके हर जालसाजी का अगर एफ आइ आर की जाए तो उनकी शायद कई पीढ़ियां जेलों में गुजर जाएंगे।

इसलिए हर उम्मीदवार के हर प्रतिनिधि को हर मशीन पर बैठकर हर कक्ष में दो व्यक्तियों को अपना लैपटॉप लेकर बैठाया जाना चाहिए जिसे कलेक्टर रोक नहीं सकता पर यह हरामखोर जालसाजी करने के लिए ना किसी को मोबाइल ले जाने देते हैं ना किसी को लैपटॉप ले जाने देते हैं ना किसी को सीट देखने देते हैं। क्योंकि उनकी सारी सच्चाई सामने आने पर उनकी जालसाजियों की एफ आइ आर कर दिए जाने पर यह पूरा का पूरा जिला प्रशासन सारे विभागों के अधिकारी जो वहां गिनती करने बैठते हैं सब के सब नौकरी से हाथ धो बैठेंगे इसलिये ना सुअर के पिल्ले जालसाज कभी एक्सेल शीट ना बनवाते हैं ना बनने देते हैं।

हर मशीन की एक्सेल शीट लेने के बाद तत्काल में उन सब की फोटो कॉपियां एक व्यक्ति को एक्सेल शीट देकर हर चक्र की गिनती की योग की एक्सरसाइज बनानी चाहिए जितने कमरों में जितनी मशीन लगी है हर राउंड की उन सब सीटों को लेकर एक हर राउंड की कुल एक्सेल सीट बनाई जानी चाहिए। उसकी मांग की जाएऔर न देने पर मतगणना को स्वीकार करने से मना करने के लिए पर्याप्त घड़ी खट्टी करनी चाहिए कि पुलिस पुलिस का जो तांडव किया जाता है वह इसलिए किया जाता है ताकि सत्ताधीशों के इशारे पर अपने मन से यह घोषणाएं करते रहें और मनचाहे तरीके से लाखों वोट से किसी को भी जिताते रहें।

बेशक कलेक्टर जब सारे उम्मीदवारों को उनके प्रतिनिधियों को बैठक बताता है तो यह कहता है की हरकत की हर मशीन जो है एक मास्टर कंप्यूटर से जुड़ी हुई है जिसमें अपने आप सारे कक्षाओं की मशीनों की गिनती पहुंच जाएगी और वह आपको एक्सेस सेट बना कर दे देंगे उसके बाद वह सारे जो कक्षा हैं वह भी एक मास्टर कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं जिसमें सारे राउंड की हर सीट की एक्सेल शीट में अपने आप पहुंच जाएगी और उसकी भी वह आपको एक्सेस सेट देगा और अंत में वह सब की हर राउंड की हर उम्मीदवार के साथ हर कक्षा की जो है कुल योग महायोग और सकल योग की एक्सेल शीट बनाकर आपको देगा और अंत में घोषणा की जाएगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी भी और मन से ही इन हरामखोरों जालसाजों ने घोषणा कर दी और यदि ईमानदार के होने और जालसाजी न करने का अगर सबूत देते हैं तो यह पिछले तीन चुनाव दो लोकसभा के और एक महापौर के चुनाव की किसी की भी एक्सेल शीट बता दें कि में किसने साइन किया किसने किसको सत्यापित करके दी।

इसलिए सभी दलों के उम्मीदवारों को जो यह घटना में बता रहा हूं इसको समझ कर संभाल कर चले और हर उम्मीदवार हर मशीन, सभी मशीनों की हर कक्ष की और सभी कक्षो की हर चक्र की कुलयोग, कुल महायोग, कुल सकल महायोग की सीट मांगे इनसे लिखित में।

न देने आना-कानी करने डराने धमकाने की दिशा में कोई भी चुनाव की घोषणा न होने दें।

यही खेलदांत मत पत्रों की गिनती में भी होता है उसमें भी सारी जैसा जिया वहां बैठे अधिकारी-कर्मचारी करते हैं इसको समझे वहां पर भी कड़ी निगरानी में और कड़ी वीडियोग्राफी में सबके वीडियो की कॉपियां मांगे और क्या-क्या किया उन्होंने उन सब की कॉपियां भी मांगे वीडियो कॉपी भी मांगे। हर कक्ष की एक्सेल शीट की हर राउंड की सब की एक्सेल शीट मांगे।

न देने पर बाहर खड़ी भीड़ जमकर नारेबाजी करें।

वीडियो ग्राफी एक्सेल शीट लेकर कोर्ट में उतरे और एफ आइ आर फाइल करें।

साप्ताहिक समय माया

यूरोपीय कंपनियाँ सैकड़ों टन घातक कीटनाशक एशियाई देशों को निर्यात कर रहे

भारत में कृषि मंत्रालय को पैसा बांट बेचो सारे घातक कीटनाशक

घातक कीटनाशक कृषि में उपयोग कर बांट रहे घातक बीमारियां

भारत का कृषि मंत्रालय यथार्थ में अमेरिकी चीनी व यूरोपीयन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कीटनाशको, खरपतवार नाशकों, अनाजों फलों तिलहन तिलहन संबंधी घातक रसायनों, जैविक तकनीकी से तैयार बीटी, वंशानुगत परिवर्तन या जेनेटिकली मोडिफाइड, उच्च नस्ल या हाइब्रिड दलहन तिलहन अनाज कपास फल मसाले आदि के विदेशी बीजों, रासायनिक खादों के उत्पादन करने वाली कंपनियों के माल की बिक्री, परीक्षण के लिए षड़यंत्रकारियों का अड्डा बन चुका है। जिसे राज्यों के कृषि मंत्री मंत्रालय भी मोटा धन लेकर आंख मींचकर खुले में किसानों को बेंचने व उनसे फसलों के उत्पादन की खुली छूट दे देते हैं। जिसके परिणाम पिछले 40 सालों से किसानों की कृषि भूमि का बंजर होना, फसलों का पैदा ना होना, फसल बिगड़ जानाआदि के संरक्षण के रूप में सामने आते हैं और जिसे हर साल भारत में 10 से 20000 किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं दूसरी तरफ उन घातक रसायनों, बीजों के प्रयोग से आमजन घातक बीमारियों का शिकार हो रहा है जिस पर ना तो भारत व उसके सभी राज्यों का कृषि व स्वास्थ्य मंत्रालय में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मिलने वाले मोटे कमीशन की खातिर हजारों करोड़ का धन हजम कर चुप बैठा हुआ है। मंत्रालय और कृषि विभाग में बैठे प्रधान सचिव, संचालक से लेकर संभागों के संयुक्त संचालक जिलों के उपसंचालक भीऐसेबीजों कीटनाशकों खरपतवार नाशकों से मोटा पैसा हजम करन केवल उत्पादन की भी पूर्ण छूट दे देते हैं इसके बारे में विदेश में जो निष्कर्ष इन घातक रसायनों के उपयोग सेजो घातक परिणाम सामने आए इस लेख में प्रस्तुत है।

स्विस एनजीओ अनअर्थड एंड पब्लिक आई का लेख

यूरोपीय कंपनियाँ सैकड़ों टन कुख्यात ज़हरीला कीटनाशक - बच्चों और अजन्मे शिशुओं में मस्तिष्क क्षति से जुड़े होने के कारण यूरोप में प्रतिबंधित - वैश्विक दक्षिण के देशों में निर्यात कर रही हैं।

स्विस एनजीओ अनअर्थड एंड पब्लिक आई द्वारा सूचना की स्वतंत्रता कानून के तहत प्राप्त दस्तावेजों से पता चला है कि पिछले साल की दूसरी छमाही में यूरोपीय कंपनियों ने 380 टन से अधिक प्रतिबंधित क्लोरपाइरीफोस कीटनाशकों के निर्यात के लिए अधिसूचनाएं जारी की थीं। वही कंपनियाँ इस वर्ष समान मात्रा में शिपिंग करने की योजना बना रही हैं।

जांच से पहली बार पता चला है कि 2020 में यूरोपीय संघ में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगने के बाद से यूरोप में क्लोरपाइरीफोस का निर्यात व्यापार जारी है। इस 'ऑर्गेनोफॉस्फेट' कीटनाशक को वैज्ञानिक सबूतों के जवाब में यूरोपीय संघ के क्षेत्रों से प्रतिबंधित कर दिया गया था कि यह 'बच्चों में प्रतिकूल न्यूरोडेवलपमेंटल परिणाम' का कारण बनता है।

दशकों के शोध से पता चलता है कि क्लोरपाइरीफोस के संपर्क से छोटे बच्चों और गर्भ में पल रहे शिशुओं को नुकसान पहुँचता है। अध्ययनों ने जन्म से पहले रसायन के संपर्क को विकासात्मक देरी, आत्म केंद्रित और आईक्यू में कमी से जोड़ा है; एक अध्ययन में पाया गया कि गर्भावस्था के दौरान माँ का रसायन के संपर्क में जितना अधिक होगा, सात साल की उम्र में उसके बच्चे का आईक्यू उतना ही कम होगा।

गरीब देशों के लिए यह उचित नहीं है कि कुछ लोगों के व्यवसाय को बनाए रखने के लिए कई लोगों के स्वास्थ्य से समझौता किया जाता रहे।

- फर्नांडो रामिरेज़ मुनोज़, कीटनाशक विशेषज्ञ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ कोस्टा रिका

इन जोखिमों के बावजूद, कंपनियां यूरोपीय संघ से कमजोर नियमों वाले गरीब देशों को क्लोरपाइरीफोस का निर्यात जारी रखती हैं। बहुराष्ट्रीय कीटनाशक कंपनियों यूपीएल और एफएमसी द्वारा बेल्जियम और डेनमार्क से भेजे गए रसायन के यूरोप के लगभग सभी 2022 निर्यात निम्न या मध्यम आय वाले देशों एलएमआईसी के लिए नियत थे।

मुख्य गंतव्य अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कोस्टा रिका थे। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, एलएमआईसी में अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग से उत्पन्न जोखिम 'लगभग बिना किसी अपवाद के' अमीर देशों की तुलना में बहुत अधिक है।

कोस्टा रिका में सेंट्रल अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज के एक अकादमिक फर्नांडो रामिरेज़ मुनोज ने कहा, 'यह गरीब देशों के लिए उचित नहीं है कि कुछ लोगों के व्यवसाय को बनाए रखने के लिए कई लोगों के स्वास्थ्य से समझौता किया जाना चाहिए।' 'प्रमाणित तथ्यों के कारण यूरोपीय संघ में क्लोरपाइरीफोस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तथ्य कम आय वाले देशों में लागू नहीं होते हैं।'

यूरोपीय संघ के व्यवहार ने 'दोहरे मानक' का प्रदर्शन किया, रामिरेज़ मुनोज़ ने कहाः 'यह स्वास्थ्य कारणों से, विशेष रूप से बच्चों में, अपने क्षेत्रों में इस पदार्थ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन इसके उत्पादन और अन्य देशों में शिपमेंट जारी रखता है जहां इसका उपयोग खाद्य उत्पादन के लिए किया जाता है। मानो इन देशों में क्लोरपाइरीफोस के संपर्क में आने वाले शिशुओं के जीवन का कोई मूल्य नहीं है।

यूरोपीय कानून में खामियों का मतलब है कि जब यूरोपीय संघ में किसी कीटनाशक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो कीटनाशक कंपनियां इसे उन देशों में बनाने और निर्यात करने के लिए स्वतंत्र रहती हैं जहां इसके उपयोग की अभी भी अनुमति है।

यूरोपीय आयोग (ईसी) ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए इस वर्ष प्रस्ताव लाने का वादा किया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि परामर्श कब शुरू होगा, नए कानून का दायरा क्या होगा और क्या इसे अधिनियमित किया जाएगा।

अपरिवर्तनीय प्रभाव

स्वास्थ्य और पर्यावरण समूहों द्वारा वर्षों के अभियान के बाद यूरोपीय संघ ने 2020 में क्लोरपाइरीफोस पर प्रतिबंध लगा दिया। जब तक प्रतिबंध पर सहमति बनी, तब तक यूके सहित विभिन्न सदस्य देशों ने पहले ही अपने क्षेत्रों में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, और अध्ययनों में कई यूरोपीय संघ के देशों में माताओं और बच्चों के मूत्र में रसायन पाया गया था - यहां तक कि स्वीडन में भी, जहां इसका उपयोग किया जाता है कभी अधिकृत नहीं किया गया था।

इस यूरोपीय संघ-व्यापी प्रतिबंध ने 'आखिरकार जीवन भर स्वास्थ्य पर पदार्थ के अपरिवर्तनीय प्रभावों को स्वीकार किया' और 'बच्चों और भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी,' स्वास्थ्य और पर्यावरण गठबंधन में स्वास्थ्य और रसायन प्रमुख नताचा सिंगोटी ने कहा।

2017 में अनानास उत्पादन में कीटनाशकों के उपयोग से होने वाले नुकसान के खिलाफ सैन जोस, कोस्टा रिका में एक विरोध प्रदर्शन में एक कार्यकर्ता नकली बैकपैक स्प्रेयर के साथ पोज देता हुआ। फोटोः एज़ेकिएल बेसेरा/एएफपी गेटी के माध्यम से सिंगोटी, जिसका एनजीओ यूरोपीय प्रतिबंध के लिए अभियान का नेतृत्व करने वालों में से था, ने कहाः 'इस कीटनाशक को तीसरे देशों में निर्यात करना अस्वीकार्य है, डऔर.स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए यूरोपीय संघ की वैश्विक प्रतिबद्धताओं की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। 'किसी पदार्थ के आंतरिक गुण देश पर निर्भर नहीं होते हैं, और लोग, विशेष रूप से बच्चों जैसे कमजोर समूह, हर जगह समान स्तर की सुरक्षा के पात्र हैं।'

प्रतिबंध लागू होने के कुछ ही समय बाद, यूरोपीय संघ ने आयातित भोजन पर मौजूद क्लोरपाइरीफोस अवशेषों की अधिकतम मात्रा को 'विश्लेषणात्मक निर्धारण की सीमा' तक कम कर दिया। वास्तव में, इसने यूरोपीय संघ में ऐसे भोजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जिसमें कीटनाशकों के किसी भी पता लगाने योग्य अंश हों।

ट्यूनीशियाई पर्यावरण विज्ञान विशेषज्ञ और देश के एसोसिएशन ऑफ एनवायर्नमेंटल एजुकेशन फॉर फ्यूचर जेनरेशन के अध्यक्ष सेमिया घरबी ने अनअर्थड और पब्लिक आई को बताया कि ट्यूनीशियाई संतरे की एक खेप को हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और वापस कर दिया गया था क्योंकि इसमें क्लोरपाइरीफोस अवशेष थे।

2022 में, यूरोपीय संघ के क्लोरपाइरीफोस निर्यात के लिए ट्यूनीशिया मात्रा के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा बाजार था।

एरिस्टा लाइफसाइंस बेनेलक्स द्वारा बेल्जियम से निर्यात किए गए 70 टन क्लोरपाइरीफोस-आधारित कीटनाशक पाइरिकल 480 के लिए उत्तरी अफ्रीकी देश इच्छित गंतव्य था। कीटनाशक की दिग्गज कंपनी यूपीएल की सहायक कंपनी बेल्जियम की कंपनी इस साल ट्यूनीशिया को फिर से इतनी ही मात्रा भेजने की योजना बना रही है।

घरबी ने कहा कि यह 'अनिवार्य' था कि प्रतिबंधित कीटनाशकों के निर्यात की यूरोपीय संघ की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, और यह 'बिल्कुल उपनिवेशवाद की परिभाषा' में फिट बैठता है, जो 'क्षेत्रों के वर्चस्व और आर्थिक शोषण को वैध बनाना' था। यह स्थिति, नैतिक और नैतिक रूप से असहनीय होने के अलावा, बाजार में असंतुलन की ओर ले जाती है।

- जकिया खट्टाबी, बेल्जियम के पर्यावरण मंत्री

ईसी ने 2020 में एक वादा किया था कि वह इस साल विधायी प्रस्ताव लाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूरोपीय संघ में प्रतिबंधित रसायनों का उत्पादन या निर्यात नहीं किया जाए। पर्यावरण आयुक्त वर्जिनिजस सिंकेविसियस ने हाल ही में नागरिक समाज समूहों को पत्र लिखकर उन्हें आश्वासन दिया कि आयोग ऐसा करने के लिए 'पूरी तरह से प्रतिबद्ध' है और '2023 के दौरान यूरोपीय संसद और परिषद के लिए एक प्रस्ताव पेश करने' की योजना बनाई है।

हालाँकि, योजना को रासायनिक लॉबी के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और प्रचारकों को डर है कि 2024 में अगले यूरोपीय संसदीय चुनावों से पहले कानून में बदलाव लाने के लिए प्रस्ताव बहुत देर से आ सकता है। योजना पर एक सार्वजनिक परामर्श पहले शुरू होने वाला था 2023 की तिमाही, लेकिन यह अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है।

2022 में यूरोपीय संघ का मुख्य क्लोरपाइरीफोस निर्यातक बेल्जियम, प्रतिबंधित कीटनाशकों के निर्यात पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध का समर्थन करता है और राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने के लिए भी कदम उठा रहा है। दिसंबर 2022 में, बेल्जियम के

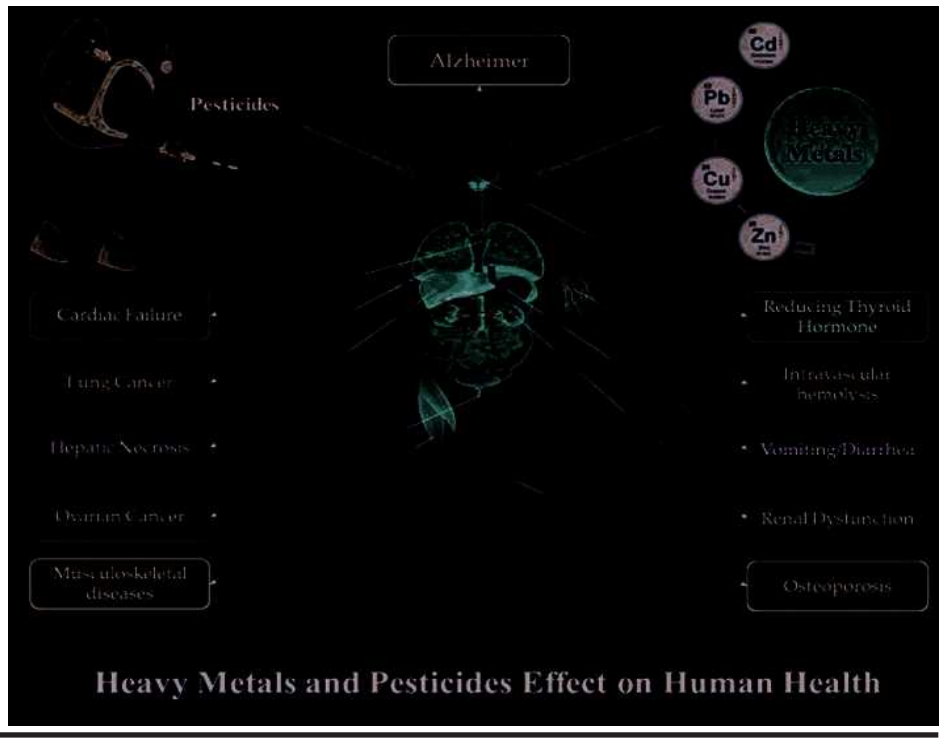

Heavy Metals and Pesticides Effect on Human Health

"कैंसर ट्रेन" और 'मौत का कारोबार'

पर्यावरण मंत्री ज़किया खट्टाबी ने एक रॉयल डिक्री का मसौदा जारी किया जो बेल्जियम से विभिन्न प्रतिबंधित कीटनाशकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा।

यह देखते हुए कि बेल्जियम प्रतिबंधित कीटनाशकों के यूरोप के मुख्य निर्यातकों में से एक था, उन्होंने उस समय कहा था: 'यह स्थिति, नैतिक रूप से और नैतिक रूप से असहनीय होने के अलावा, तीसरे देशों से अनुचित प्रतिस्पर्धा के साथ बाजार में असंतुलन पैदा करती है जो कुछ रसायनों का उपयोग कर सकते हैं।

'यूरोपीय उपभोक्ता की कीमत पर भी इसका बूमरैंग प्रभाव पड़ता है, जो अपनी थाली में आयातित भोजन पाता है जिसे इन हानिकारक निर्यातित पदार्थों के साथ इलाज किया गया है।'

खट्टाबी के एक प्रवक्ता ने अनअर्थड और पब्लिक आई को बताया कि उनका इरादा विधायी प्रक्रिया के अगले चरण के दौरान क्लोरपाइरीफोस निर्यात पर प्रतिबंध को शामिल करने के लिए रॉयल डिक्री को अद्यतन करने का है। यह डिक्री लगभग छह महीने में लागू होने की उम्मीद है।

हालाँकि, फ्रांस में इसी तरह के प्रतिबंध की अनअर्थड और पब्लिक आई द्वारा हाल ही में की गई जांच में पाया गया कि जहां व्यक्तिगत यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा निर्यात प्रतिबंधों का प्रभाव पड़ता है, वहीं उनकी सीमाएं भी हैं। यूरोपीय संघ-व्यापक प्रतिबंध के अभाव में, बहुराष्ट्रीय कीटनाशक कंपनियाँ अपने निर्यात व्यापार को अन्य सदस्य राज्यों में सहायक कंपनियों में स्थानांतरित करके राष्ट्रीय प्रतिबंधों को अपना सकती हैं।

उच्च स्वास्थ्य जोखिम

वर्तमान में यूरोप के प्रतिबंधित कीटनाशकों के निर्यातकों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में से एक यूरोपीय संघ का 'पूर्व सूचित सहमति' (पीआईसी) विनियमन है। नियमों के इस सेट के तहत, एक निर्यातक देश को आयातक देशों को पूर्व चेतावनी देने की आवश्यकता होती है यदि वह उन्हें ऐसे कीटनाशक भेजने का इरादा रखता है जो उसके अपने खेतों पर प्रतिबंधित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित हैं।

इसका मतलब यह है कि जब भी कोई कंपनी प्रतिबंधित कीटनाशक भेजना चाहती है तो उसे आयातक देश के अधिकारियों को भेजने के लिए एक 'निर्यात अधिसूचना' दस्तावेज़ तैयार करना होगा। 1 जुलाई 2022 को क्लोरपाइरीफोस इन नियमों के अधीन हो गया।

सूचना कानूनों की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए, अनअर्थड और पब्लिक आई ने 2022 में क्लोरपाइरीफोस शिपमेंट के लिए जारी की गई प्रत्येक निर्यात अधिसूचना प्राप्त की, और उनमें से अधिकांश इस चालू वर्ष में अब तक जारी की गईं।

ये दस्तावेज़ एक सटीक रिकॉर्ड नहीं हैं, लेकिन वे इस खतरनाक कीटनाशक में यूरोपीय संघ के निरंतर व्यापार के लिए उपलब्ध सबसे सटीक पेपर ट्रेल हैं।

वे बताते हैं कि 2022 की दूसरी छमाही में, बेल्जियम यूरोप का क्लोरपाइरीफोस का अब तक का सबसे बड़ा निर्यातक था। यूपीएल की बेल्जियम सहायक कंपनी ने 349 टन क्लोरपाइरीफोस कीटनाशकों के निर्यात को अधिसूचित किया, जो कुल यूरोपीय का 91% है।

ये निर्यात 16 देशों के लिए किया गया था, जिनमें मुख्य गंतव्य अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, कजाकिस्तान, बांग्लादेश और कोस्टारिका थे। अन्य आयातक देशों में डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर और आर्मेनिया शामिल थे। यूपीएल ने पहले ही 2023 में बेल्जियम से 313 टन क्लोरपाइरीफोस निर्यात करने की योजना जारी कर दी है। गंतव्यों की सूची काफी हद तक वही है, हालांकि इस साल इसमें सर्बिया भी शामिल है।

इस वर्ष की शुरुआत में ट्यूनिस, ट्यूनीशिया में एक किसान खट्टे फल एकत्र करता है। उत्तरी अफ्रीकी देश ने हाल ही में संतरे की एक खेप को यूरोपीय संघ द्वारा अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उनमें क्लोरपाइरीफोस था - एक कीटनाशक जो यूरोपीय संघ ट्यूनीशिया को निर्यात करता है।

यूपीएल के एक प्रवक्ता ने कहा: 'यूपीएल सभी डबेल्जियम, यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है।'

दस्तावेज़ों से पता चलता है कि डेनमार्क क्लोरपाइरीफोस-आधारित कीटनाशकों का निर्माण और निर्यात भी कर रहा है। 2022 में, डेनिश कंपनी केमिनोवा - जो अब कीटनाशक दिग्गज एफएमसी की सहायक कंपनी है - ने अधिकारियों को 33.2 टन क्लोरपाइरीफोस-आधारित निर्यात के बारे में सूचित किया। इसमें से 2 टन लेबनान के लिए थे, और शेष 31.2 टन पाकिस्तान के लिए थे।

अब तक 2023 में, चेमिनोवा ने पहले ही पाकिस्तान को 55 टन और शिपमेंट अधिसूचित कर दिया है - एक ऐसा देश जहां अध्ययनों से पता चला है कि क्लोरपाइरीफोस और अन्य ऑर्गनोफॉस्फेट के संपर्क से चयापचय संबंधी विकार का खतरा बढ़ जाता है, और इन कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग इतना प्रचलित है कि धूल प्रमुख शहरों में फार्म 'उच्च स्वास्थ्य जोखिम' पैदा करते हैं।

क्योंकि क्लोरपाइरीफोस मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास को नुकसान पहुंचाता है, यह ईयू-निर्मित कीटनाशक अगली पीढ़ी में संज्ञानात्मक कौशल को नुकसान पहुंचाता है।

- फिलिप ग्रांडजीन, पर्यावरण चिकित्सा के प्रोफेसर, डेनमार्क

एफएमसी के एक प्रवक्ता ने अनअर्थड से पुष्टि की कि कंपनी डेनमार्क में 'थोड़ी मात्रा में क्लोरपाइरीफोस युक्त उत्पाद तैयार कर रही है'।

2021 के बाद से, खाद्य फसलों पर क्लोरपाइरीफोस के उपयोग को एफएमसी के गृह देश अमेरिका में भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, जहां यूरोपीय संघ की तुलना में कीटनाशकों के लिए कुख्यात नियम हैं।

हालाँकि, एफएमसी के प्रवक्ता ने तर्क दिया कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के मानदंडों के तहत, 'क्लोरपाइरीफोस एक एचएचपी डअत्यधिक खतरनाक कीटनाशक. नहीं है'।

उन्होंने आगे कहा: 'उत्पादों को पंजीकृत किया जा सकता है डलाइसेंस प्राप्त. और कुछ देशों में फसलों पर उपयोग के लिए प्रभावी, जैसा कि उनके लेबल पर निर्देशित है, भले ही वे उत्पाद जलवायु, फसल और कीटों के अंतर के कारण अन्य देशों में पंजीकृत न हों। सभी फसल सुरक्षा उत्पादों का अधिकारियों द्वारा कड़ाई से परीक्षण और विनियमन किया जाता है, और लेबल निर्देशों के अनुसार उपयोग किए जाने पर एफएमसी फसल सुरक्षा उत्पादों को सुरक्षित माना जाता है।

'फिर भी, क्लोरपाइरीफोस में एफएमसी के वैश्विक पोर्टफोलियो का एक छोटा और छोटा हिस्सा शामिल है।'

उन्होंने बताया कि अनअर्थड और पब्लिक आई द्वारा उद्धृत आंकड़े निर्यात के लिए अधिसूचित क्लोरपाइरीफोस-आधारित कीटनाशकों की कुल मात्रा के लिए थे, और इसलिए निर्यात किए गए रसायन का वजन कम था।

एफएमसी डेनमार्क से जिन कीटनाशकों का निर्यात करती है उनमें क्लोरपाइरीफोस की सांद्रता 30 से 44 प्रतिशत तक होती है।

फिलिप ग्रांडजीन दक्षिणी डेनमार्क विश्वविद्यालय में पर्यावरण चिकित्सा के प्रोफेसर हैं, और उन वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने उद्योग-वित्त पोषित विष विज्ञान के साथ समस्याओं को उजागर किया था जिसका उपयोग यूरोप में क्लोरपाइरीफोस के प्राधिकरण का समर्थन करने के लिए किया गया था।

उन्होंने अनअर्थड और पब्लिक आई को बताया: 'चूँकि क्लोरपाइरीफोस प्रारंभिक मस्तिष्क विकास को नुकसान पहुँचाता है, यह ईयू-निर्मित कीटनाशक अगली पीढ़ी में संज्ञानात्मक कौशल को नुकसान पहुँचाता है।

'और हमारी पीढ़ी ने जो क्षति पहुंचाई है, उसे देखते हुए, हमें भविष्य के बच्चों की बुद्धि की यथासंभव रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें हमारे द्वारा पैदा की गई सभी क्षति के लिए स्मार्ट समाधान तैयार करने की आवश्यकता है।'

हमने यह कैसे किया

अनअर्थड और पब्लिक आई ने 2022 की दूसरी छमाही और 2023 की शुरुआत में क्लोरपाइरीफोस युक्त उत्पादों के लिए उस बिंदु तक जारी की गई प्रत्येक निर्यात अधिसूचना प्राप्त करने के लिए यूरोपीय रसायन एजेंसी (ईसीएचए) और बेल्जियम सरकार को सूचना की स्वतंत्रता के अनुरोध दायर किए।

ये ऐसे दस्तावेज़ हैं जिन्हें कंपनियों को यूरोपीय संघ के पूर्व सूचित सहमति विनियमन की शर्तों के तहत गैर-यूरोपीय संघ के देशों में प्रतिबंधित कीटनाशकों का निर्यात करने से पहले जारी करने की आवश्यकता होती है, जो संयुक्त राष्ट्र के रॉटरडैम कन्वेंशन की शर्तों पर आधारित है।

दस्तावेज़ शिपमेंट से पहले आयात करने वाले देश के अधिकारियों को जारी किए जाते हैं, और निर्यात की जाने वाली अनुमानित राशि का संकेत देते हैं। इसलिए वे एक सटीक रिकॉर्ड नहीं हैं: ऐसे समय होते हैं जब अंततः निर्यात की गई राशि अधिसूचना पर दी गई राशि से अधिक या कम होती है; ऐसे भी समय होते हैं जब अधिसूचित निर्यात अंततः नहीं होते हैं। हालाँकि, वे प्रतिबंधित कीटनाशकों में यूरोपीय संघ के निर्यात व्यापार का सबसे सटीक रिकॉर्ड हैं।

अनअर्थड एंड पब्लिक आई का विश्लेषण पूरी तरह से आयातक देशों में 'पौधे संरक्षण उपयोग' के लिए प्रतिबंधित कीटनाशकों के निर्यात पर केंद्रित है। आयातक देश में जैवनाशक या अन्य गैर-कृषि उपयोग के लिए सभी निर्यातों को विश्लेषण से बाहर रखा गया था।

छोटे निर्माता व विक्रेताओं को खत्म करने का षड्यंत्र

पेज 8 का शेष

पर सभी खाद्य विक्रेताओं व्यवसाईयों उद्योगों को मोटी फीस के साथ इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होने की मोटी फीस जमा करने, उस अधिनियम के अंतर्गत सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करने मोटा धन हर महीने खाद्य निरीक्षकों अधिकारियों को बांटने का षड्यंत्रकरने व्यवस्था कर दी गई। यही हाल औषधि निरीक्षकों का भी है वह छोटी औषधि निर्माता फैक्ट्रियों, औषधि चिकित्सा सामग्री विक्रेताओं से नियमित जांच, औषधीयां का विवरण के अनुसार तत्वों के ना पाए जाने, नमूने लेने, समय बाधित होने उनको फ्रीज करने न करने, जिसमें विक्रेताओं की उनके विपरीत टिप्पणी न करने से महिना वसूली के कारण, अभय मिला होता है। पैथो लेब, ब्लड बैंक भी इन्हीं की जांच के अंतर्गत होने से इनसे भी महीना वसूली होती है।

मप्र के अधिकांश जिलों में इंदौर भोपाल को छोड़ जहां 5 से ज्यादा निरीक्षक पदस्थ हैं। कई निरीक्षकों के पास तो निरीक्षकों की कमी व औषधि नियंत्रक व स्वास्थ्य मंत्री को मोटा धन बांटने मासिक चुकाने के कारण, 2-3 जिलों के प्रभार भी हैं। इंदौर में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक को जिसके अंतर्गत दवा बाजार है, 500 थोक औषधि दुकानों से रु. 1000 प्रति दुकान महीना मिलने के कारण, सब निरीक्षकों की निगाह वरिष्ठता व दवा निरीक्षक के प्रभार पाने की होती है।

अब चूंकि मोटी वसूली करने के प्रावधान उस कानून में है तो स्वाभाविक बात है खाद्य अधिकारियों औषधि निरीक्षकों की चारों तरफ कमाई के कारण अधिकांश खाद्य अधिकारी जो सभी लाखों की कर के मालिक हैं? बेशक उनके नाम पर नहीं, प्राप्त वेतन का 30 से 50% स्वयं के व्यय का पेट्रोल खर्च कर लूट की कमाई का आनंद ले रहे हैं यही कारण यह हरामखोर जालसाज डकैतों की फौज लाखों रुपए महीना कलेक्टर सीएमएचओ अपने नियंत्रक और मंत्री तक को बांटने में स्थानांतरण अच्छी पदस्थी के लिए खर्च करने से नहीं चूकती।

यही कारण है की सूचना के अधिकार में जानकारी देने के नाम पर जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधि., औषधि सौंदर्य प्रशाधन अधिक.1940 व मप्र सरकार के अंतर्गत सारे विभागों के कार्यालयीन कार्य बिना कागजों के कंप्यूटर पर व ऑनलाइन किए जाने की घोषणा सन 2010 से कर दी गई थी। जबकि आवेदन में स्पष्ट रूप से सूचना अधिकार अधि.05 धारा 2 के (ज) iv के सीडी में देने या धारा 4 के 25 बिंदुओं की जानकारी के अंतर्गत ऑनलाइन देने का प्रावधान होने व लिख कर मांग किये जाने के विपरीत फोटो कॉपी देने के लिए हजारों रुपए की मांग की जाती है। अपील करने पर इंदौर-उज्जैन संभाग के 15 जिलों के सीएमएचओ चूंकि सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी और औषधि निरीक्षक महीना बांटते हैं। इसलिए अधिकांश अपीलों में यह कहकर जानकारी देने से बचा लिया जाता है। की चाह गई जानकारीका कंप्यूटर पर संधान नहीं किया जाता है सारी जानकारी के लिए फोटोकॉपी के शुल्क के रूप में मांगे गए हजारों रु. जमा कीजिए तभी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस विभाग की चारों तरफ घोर भ्रष्टाचार लूट छुपाने व वसूली के कारण साइट खुलती ही नहीं। जिसमें 25 बिंदुओं की जानकारी स्वयं खाद्य एवं औषधि नियंत्रक जो भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी होने के कारण अपलोड करने उसे हर 3 महीने में अपडेट करने का कार्य किया जाना चाहिए। परंतु 18 साल में कभी भी ना तो उनकी साइट खुलती हैं। और ना ही जानकारी मिलती है। अधिकांश औषधि निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी करोड़पति हैं इन हरामखोरों पर अचानक छापे डाल संपत्तियों की जांच की जाए साथ ही मेरे लेख की सच्चाई की पुष्टि करने इनके अधिकृत वन अधिकृत विभाग के पास पंजीकृत अपंजीकृत मोबाइल नंबर की पेगासस सॉफ्टवेयर से अगर जासूसी की जाए तो उनके गृह नगर से लेकर पदस्ती के जिले में करोड़ों की संपत्तियां मिल सकती हैं।

केंद्र सरकार ने 20 करोड रुपए से ज्यादा का उत्पादन करने वाली सभी बड़ी यूनिट को अपने नियंत्रण में लेकर खुले में जाल साजी पूर्णअमानक स्तर के कम मात्रा और प्रतिशत के तत्वों से दवाई बनाने वालों को अपने अधीन कर केंद्र के निरीक्षक मोटी कमाई कर रहे है।

साप्ताहिक समय माया

भारत में 140 करोड़ मोबाइल सभी साइबर अपराधियों के निशाने पर

पेज 1 का शेष

साइबर अपराधी चोरी और पुनर्विक्रय के लिए किसी व्यक्ति की निजी जानकारी या कॉर्पोरेट डेटा को लक्षित कर सकते हैं। जैसा कि कई कर्मचारी महामारी के कारण दूरस्थ कार्य दिनचर्या में बस जाते हैं, 2021 में साइबर अपराधों की आवृत्ति बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बैकअप डेटा की सुरक्षा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

साइबर अपराध को परिभाषित करना अमेरिकी न्याय विभाग डीओजे साइबर अपराध को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है:

• ऐसे अपराध जिनमें कंप्यूटिंग डिवाइस लक्ष्य है -उदाहरण के लिए, नेटवर्क पहुंच प्राप्त करना;

• ऐसे अपराध जिनमें कंप्यूटर को एक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है - उदाहरण के लिए, सेवा से इनकार अदए हमला शुरू करने के लिए; और

• ऐसे अपराध जिनमें कंप्यूटर का उपयोग किसी अपराध के सहायक के रूप में किया जाता है - उदाहरण के लिए, अवैध रूप से प्राप्त डेटा को संग्रहीत करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना।

काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, जिसमें अमेरिका एक हस्ताक्षरकर्ता है, साइबर क्राइम को दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें डेटा का अवैध अवरोधन, सिस्टम हस्तक्षेप जो नेटवर्क अखंडता और उपलब्धता से समझौता करता है, और कॉपीराइट उल्लंघन शामिल हैं।

इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता ने साइबर अपराध गतिविधियों की मात्रा और गति में वृद्धि को सक्षम किया है क्योंकि अपराध करते समय अपराधी को अब शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट की गति, सुविधा, गुमनामी और सीमाओं की कमी कंप्यूटर-आधारित वित्तीय अपराधों जैसे रैंसमवेयर, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ-साथ पीछा करना और धमकाने जैसे अपराधों को अंजाम देना आसान बनाती है।

साइबर आपराधिक गतिविधि अपेक्षाकृत कम तकनीकी कौशल वाले व्यक्तियों या समूहों द्वारा, या उच्च संगठित वैश्विक आपराधिक समूहों द्वारा की जा सकती है जिनमें कुशल डेवलपर्स और प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले अन्य लोग शामिल हो सकते हैं। पहचान और अभियोजन की संभावनाओं को और कम करने के लिए, साइबर अपराधी अक्सर कमजोर या अस्तित्वहीन साइबर अपराध कानूनों वाले देशों में काम करना चुनते हैं।

साइबर क्राइम कैसे काम करता है

डिजिटल डेटा, अवसर और मकसद जहां भी हो, साइबर अपराध हमले शुरू हो सकते हैं। साइबर अपराधियों में साइबरबुलिंग में शामिल अकेले उपयोगकर्ता से लेकर चीन की खुफिया सेवाओं जैसे राज्य-प्रायोजित अभिनेता तक सभी शामिल हैं।

साइबर अपराध आमतौर पर शून्य में नहीं होते हैं; वे, कई मायनों में, प्रकृति में वितरित हैं। यानी, साइबर अपराधी आमतौर पर अपराध को अंजाम देने के लिए अन्य कलाकारों पर भरोसा करते हैं। चाहे वह कोड बेचने के लिए डार्क वेब का उपयोग करने वाले मैलवेयर का निर्माता हो, एस्क्रो में आभासी धन रखने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी ब्रोकरों का उपयोग करने वाले अवैध फार्मास्यूटिकल्स के वितरक हों या बौद्धिक संपदा (आईपी) चुराने के लिए प्रौद्योगिकी उप ठेकेदारों पर भरोसा करने वाले राज्य के खतरे वाले अभिनेता हों।

साइबर अपराधी अपने साइबर हमलों को अंजाम देने के लिए विभिन्न आक्रमण वैक्टरों का उपयोग करते हैं और पता लगाने और गिरफ्तारी से बचते हुए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार नए तरीकों और तकनीकों की तलाश कर रहे हैं। साइबर अपराधी अक्सर मैलवेयर और अन्य प्रकार के सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, लेकिन अधिकांश प्रकार के साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए सोशल इंजीनियरिंग अक्सर एक महत्वपूर्ण घटक होता है। फ़िशिंग ईमेल कई प्रकार के साइबर अपराध के लिए एक और महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन विशेष रूप से लक्षित हमलों के लिए, जैसे बिजनेस ईमेल समझौता बीईसी, जिसमें हमलावर ईमेल के माध्यम से, एक व्यवसाय के मालिक का रूप धारण करने का प्रयास करता है ताकि कर्मचारियों को फर्जी चालान का भुगतान करने के लिए राजी किया जा सके। .

साइबर क्राइम के प्रकार

जैसा कि ऊपर बताया गया है, साइबर अपराध कई प्रकार के होते हैं। अधिकांश साइबर अपराध हमलावरों द्वारा वित्तीय लाभ की उम्मीद से किए जाते हैं, हालांकि साइबर अपराधियों के भुगतान पाने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के साइबर अपराधों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• **साइबरएक्सटॉर्शन:** एक अपराध जिसमें हमला या हमले की धमकी के साथ-साथ हमले को रोकने के लिए पैसे की मांग शामिल है। साइबरएक्सटॉर्शन का एक रूप रैनसमवेयर हमला है। यहां, हमलावर किसी संगठन के सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर लेता है और उसके दस्तावेज़ों और फ़ाइलों - संभावित मूल्य की किसी भी चीज़ - को एन्क्रिप्ट कर देता है, जिससे फिरौती का भुगतान होने तक डेटा अप्राप्य हो जाता है। आमतौर पर, यह क्रिप्टोकरेंसी के किसी रूप में होता है, जैसे बिटकॉइन।

• **क्रिप्टोजैकिंग:** एक हमला जो उपयोगकर्ता की सहमति के बिना ब्राउज़र के भीतर क्रिप्टोकरेंसी को माइन करने के लिए स्क्रिप्ट का उपयोग करता है। क्रिप्टोजैकिंग हमलों में पीड़ित के सिस्टम में क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग सॉफ़्टवेयर लोड करना शामिल हो सकता है। हालाँकि, कई हमले जावास्क्रिप्ट कोड पर निर्भर करते हैं जो ब्राउज़र में खनन करता है यदि उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में दुर्भावनापूर्ण साइट पर कोई टैब या विंडो खुली हो। किसी मैलवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रभावित पेज को लोड करने से इन-ब्राउज़र माइनिंग कोड निष्पादित हो जाता है।

• **पहचान की चोरी:** एक हमला जो तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने के लिए कंप्यूटर तक पहुंचता है, जिसका उपयोग वे उस व्यक्ति की पहचान चुराने या बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड जैसे उनके मूल्यवान खातों तक पहुंचने के लिए करते हैं। साइबर अपराधी डार्कनेट बाज़ारों पर पहचान की जानकारी खरीदते और बेचते हैं, वित्तीय खातों के साथ-साथ वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं, वेबमेल, वीडियो और ऑडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन नीलामी और बहुत कुछ जैसे अन्य प्रकार के खातों की पेशकश करते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी पहचान चोरों का एक और लगातार लक्ष्य है।

• **क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी:** ऐसा हमला जो तब होता है जब हैकर्स अपने ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड और/या बैंकिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए खुदरा विक्रेताओं के सिस्टम में घुसपैठ करते हैं। चुराए गए भुगतान कार्डों को डार्कनेट बाजारों में थोक में खरीदा और बेचा जा सकता है, जहां बड़े पैमाने पर क्रेडिट कार्ड चुराने वाले हैकिंग समूह निचले स्तर के साइबर अपराधियों को बेचकर लाभ कमाते हैं, जो व्यक्तिगत खातों के खिलाफ क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के माध्यम से लाभ कमाते हैं।

• **साइबर जासूसी:** एक अपराध जिसमें एक साइबर अपराधी शामिल होता है जो किसी सरकार या अन्य संगठन द्वारा रखी गई गोपनीय जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सिस्टम या नेटवर्क को हैक करता है। हमले लाभ या विचारधारा से प्रेरित हो सकते हैं। साइबर जासूसी गतिविधियों में डेटा इकट्ठा करने, संशोधित करने या नष्ट करने के लिए हर प्रकार के साइबर हमले शामिल हो सकते हैं, साथ ही किसी लक्षित व्यक्ति या समूहों पर जासूसी करने और संचार की निगरानी करने के लिए वेबकैम या क्लोज-सर्किट टीवी (सीसीटीवी) कैमरे जैसे नेटवर्क से जुड़े उपकरणों का उपयोग करना शामिल हो सकता है। ईमेल, पाठ संदेश और त्वरित संदेश।

• **सॉफ्टवेयर चोरी:** एक ऐसा हमला जिसमें व्यावसायिक या व्यक्तिगत उपयोग के इरादे से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की गैरकानूनी नकल, वितरण और उपयोग शामिल है। ट्रेडमार्क उल्लंघन, कॉपीराइट उल्लंघन और पेटेंट उल्लंघन अक्सर इस प्रकार के साइबर अपराध से जुड़े होते हैं।

• **एक्ज़िट स्कैम:** इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि डार्क वेब ने एक पुराने अपराध के डिजिटल संस्करण को जन्म दिया है जिसे एक्ज़िट स्कैम के नाम से जाना जाता है। आज के रूप में, डार्क वेब प्रशासक मार्केटप्लेस एस्क्रो खातों में रखी आभासी मुद्रा को अपने खातों में स्थानांतरित कर देते हैं - अनिवार्य रूप से, अपराधी अन्य अपराधियों से चोरी करते हैं। साइबर अपराध के सामान्य उदाहरण आमतौर पर देखे जाने वाले कुछ साइबर अपराध हमलों में वितरित DoS (DDoS) हमले शामिल हैं, जिनका उपयोग अक्सर सिस्टम और नेटवर्क को बंद करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का हमला कनेक्शन अनुरोधों का जवाब देने की क्षमता को बढ़ाकर नेटवर्क के स्वयं के संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है।

DDoS हमले कभी-कभी केवल दुर्भावनापूर्ण कारणों से या साइबर वसूली योजना के हिस्से के रूप में किए जाते हैं, लेकिन उनका उपयोग पीड़ित संगठन को उसी समय किए गए किसी अन्य हमले या शोषण से विचलित करने के लिए भी किया जा सकता है। सिस्टम और नेटवर्क को मैलवेयर से संक्रमित करना ऐसे हमले का एक उदाहरण है जिसका उपयोग सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम, सॉफ़्टवेयर या सिस्टम पर संग्रहीत डेटा को नुकसान पहुंचाकर किया जा सकता है।

रैनसमवेयर हमले समान हैं, लेकिन मैलवेयर फिरौती का भुगतान होने तक पीड़ित सिस्टम को एन्क्रिप्ट या बंद करके कार्य करता है। फ़िशिंग अभियानों का उपयोग कॉर्पोरेट नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए किया जाता है। यह किसी संगठन में उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजकर, उन्हें अटैचमेंट डाउनलोड करने या लिंक पर क्लिक करने के लिए लुभाकर किया जा सकता है, जो फिर उनके सिस्टम में और उनके सिस्टम के माध्यम से उनकी कंपनी के नेटवर्क में वायरस या मैलवेयर फैलाते हैं।

क्रेडेंशियल हमले तब होते हैं जब कोई साइबर अपराधी पीड़ित के सिस्टम या व्यक्तिगत खातों के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड चुराने या अनुमान लगाने का लक्ष्य रखता है। इन्हें कीलॉगर सॉफ़्टवेयर स्थापित करके या सॉफ़्टवेयर या हार्डवेयर में कमजोरियों का फायदा उठाकर क्रूर-बल के हमलों के माध्यम से किया जा सकता है जो पीड़ित की साख को उजागर कर सकता है। साइबर अपराधी सामग्री को बदलने या हटाने या प्राधिकरण के बिना डेटाबेस तक पहुंचने या संशोधित करने के लिए किसी वेबसाइट को हाईजैक करने का प्रयास भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक हमलावर किसी वेबसाइट में दुर्भावनापूर्ण कोड डालने के लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल इंजेक्शन शोषण का उपयोग कर सकता है,

व्यवसायों पर साइबर अपराध का प्रभाव

साइबर अपराध की वास्तविक लागत का सटीक आकलन करना कठिन है। 2018 में, ईमी ने साइबर अपराध के आर्थिक प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अनुमान लगाया गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावित वार्षिक लागत लगभग $600 बिलियन थी, जो 2014 में $45 बिलियन से अधिक थी।

जबकि साइबर अपराध के कारण वित्तीय नुकसान महत्वपूर्ण हो सकता है, व्यवसायों को आपराधिक साइबर हमलों के परिणामस्वरूप अन्य विनाशकारी परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• सुरक्षा उल्लंघन के बाद निवेशकों की धारणा को नुकसान होने से कंपनी के मूल्य में गिरावट आ सकती है।

• संभावित शेयर मूल्य में गिरावट के अलावा, साइबर हमले के परिणामस्वरूप व्यवसायों को उधार लेने की लागत में वृद्धि और अधिक पूंजी जुटाने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

• संवेदनशील ग्राहक डेटा के नुकसान के परिणामस्वरूप उन कंपनियों को जुर्माना और सजा हो सकती है जो अपने ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा करने में विफल रही हैं। डेटा उल्लंघन पर व्यवसायों पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

• साइबर हमले के बाद क्षतिग्रस्त ब्रांड पहचान और प्रतिष्ठा की हानि किसी कंपनी में ग्राहकों के विश्वास और उस कंपनी की अपने वित्तीय डेटा को सुरक्षित रखने की क्षमता को कमजोर करती है। साइबर हमले के बाद, कंपनियां न केवल मौजूदा ग्राहकों को खो देती हैं, बल्कि वे नए ग्राहकों को हासिल करने की क्षमता भी खो देती हैं।

• व्यवसायों को आपराधिक साइबर हमले से प्रत्यक्ष लागत भी उठानी पड़ सकती है, जिसमें बढ़ी हुई बीमा प्रीमियम लागत और घटना की प्रतिक्रिया और उपचार के लिए साइबर सुरक्षा कंपनियों को काम पर रखने की लागत, साथ ही जनसंपर्क पीआर और हमले से संबंधित अन्य सेवाएं शामिल हैं।

राष्ट्रीय रक्षा पर साइबर अपराध का प्रभाव

साइबर अपराधों का सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कंप्यूटर अपराध डीओजे की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बन जाएगा। अमेरिका में, संघीय स्तर पर, संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) साइबर डिवीजन डीओजे के भीतर की एजेंसी है जिस पर साइबर अपराध से निपटने का आरोप है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग डीएचएस साइबरस्पेस की सुरक्षा और लचीलेपन को मजबूत करने को एक महत्वपूर्ण होमलैंड सुरक्षा मिशन के रूप में देखता है। अमेरिकी गुप्त सेवा यूएसएसएस और अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) जैसी एजेंसियों के पास साइबर अपराध से निपटने के लिए समर्पित विशेष प्रभाग हैं।

यूएसएसएस की इलेक्ट्रॉनिक अपराध टास्क फोर्स (ईसीटीएफ) उन मामलों की जांच करती है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अपराध शामिल हैं, विशेष रूप से देश के वित्तीय और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले। यूएसएसएस राष्ट्रीय कंप्यूटर फोरेंसिक संस्थान (एनसीएफआई) भी चलाता है, जो राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन, न्यायाधीशों और अभियोजकों को कंप्यूटर फोरेंसिक में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र IC3, FBI, नेशनल व्हाइट कॉलर क्राइम सेंटर NW3C और ब्यूरो ऑफ जस्टिस असिस्टेंस BJA के बीच एक साझेदारी, इंटरनेट अपराध के पीड़ितों या इच्छुक तीसरे पक्षों से ऑनलाइन शिकायतें स्वीकार करती है।

साइबर क्राइम को कैसे रोकें

हालांकि साइबर अपराध को पूरी तरह से खत्म करना और पूर्ण इंटरनेट सुरक्षा सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सकता है, व्यवसाय सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को सुरक्षित करने के लिए गहन रक्षा दृष्टिकोण का उपयोग करके एक प्रभावी साइबर सुरक्षा रणनीति बनाए रखकर इसके जोखिम को कम कर सकते हैं।

निम्नलिखित कदमों से साइबर अपराध के जोखिमों को कम किया जा सकता है:

• व्यवसाय और कर्मचारियों के लिए स्पष्ट नीतियां और प्रक्रियाएं विकसित करना;

• इन नीतियों और प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया योजनाएँ बनाएं;

• सिस्टम और कॉर्पोरेट डेटा की सुरक्षा के तरीके के बारे में मौजूद सुरक्षा उपायों की रूपरेखा तैयार करें;

• दो-कारक प्रमाणीकरण 2FA ऐप्स या भौतिक सुरक्षा कुंजी का उपयोग करें;

• जब संभव हो तो प्रत्येक ऑनलाइन खाते पर 2FA सक्रिय करें;

• वित्तीय प्रबंधक से बात करके पैसे भेजने के अनुरोधों की प्रामाणिकता को मौखिक रूप से सत्यापित करें;

• घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली आईडीएस नियम बनाएं जो कंपनी ईमेल के समान एक्सटेंशन

वाले ईमेल को चिह्नित करें;

• यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अनुरोध सामान्य से बाहर हैं, धन हस्तांतरण के लिए सभी ईमेल अनुरोधों की सावधानीपूर्वक जांच करें;

• साइबर सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं पर कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षित करें और सुरक्षा उल्लंघनों की स्थिति में क्या करें;

• सभी सॉफ़्टवेयर रिलीज़ अपडेट या पैच के साथ वेबसाइटों, एंडपॉइंट डिवाइस और सिस्टम को चालू रखें; और

• रैंसमवेयर हमले या डेटा उल्लंघन की स्थिति में क्षति को कम करने के लिए नियमित रूप से डेटा और जानकारी का बैकअप लें।

सूचना सुरक्षा और साइबर अपराध हमलों के प्रतिरोध को स्थानीय हार्ड डिस्क और ईमेल प्लेटफ़ॉर्म को एन्क्रिप्ट करके, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करके और एक निजी, सुरक्षित डोमेन नाम सिस्टम (डीएनएस) सर्वर का उपयोग करके भी बनाया जा सकता है।

साइबर अपराध कानून और एजेंसियां

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, साइबर अपराध हमलों की निगरानी और प्रबंधन से विशेष रूप से निपटने के लिए विभिन्न अमेरिकी सरकारी एजेंसियों की स्थापना की गई है। एफबीआई का साइबर डिवीजन साइबर अपराधियों, आतंकवादियों या विदेशी विरोधियों के हमलों से निपटने के लिए प्रमुख संघीय एजेंसी है। डीएचएस के भीतर साइबर सुरक्षा और बुनियादी ढांचा सुरक्षा एजेंसी (सीआईएसए) है। यह समूह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए निजी क्षेत्र और सरकारी संगठनों के बीच समन्वय करता है।

इसके अलावा, साइबर अपराध केंद्र C3 कंप्यूटर-आधारित तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है जो आव्रजन और सीमा शुल्क अधिकारियों के होमलैंड सुरक्षा जांच HSI पोर्टफोलियो में शामिल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जांच का समर्थन करता है। C3 उन साइबर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनमें सीमा पार अवैध गतिविधियां शामिल हैं। यह एचएसआई क्षेत्राधिकार के भीतर सभी साइबर अपराधों को खोजने और लक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। C3 में साइबर अपराध इकाई (सीसीयू), बाल शोषण जांच इकाई (सीईआईयू) और कंप्यूटर फोरेंसिक यूनिट सीएफयू शामिल हैं। साइबर अपराध से निपटने के लिए स्थापित एजेंसियों के अलावा विभिन्न कानून और कानून बनाए गए हैं। 2015 में, ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी ने साइबर क्राइम रिपॉजिटरी जारी की, जो एक केंद्रीय डेटाबेस है जिसमें साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर कानून, पिछले निष्कर्ष और केस कानून शामिल हैं। साइबर क्राइम रिपॉजिटरी का इरादा साइबर अपराधियों पर मुकदमा चलाने और उन्हें रोकने के प्रयासों में देशों और सरकारों की सहायता करना है।

साइबर अपराध से निपटने वाला कानून आम जनता पर लागू हो सकता है, या यह क्षेत्र-विशिष्ट हो सकता है, केवल कुछ प्रकार की कंपनियों तक विस्तारित हो सकता है। उदाहरण के लिए, ग्राम-लीच-ब्लिली अधिनियम जीएलबीए वित्तीय संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करता है और लिखित नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को नियंत्रित करता है, जिससे ग्राहक रिकॉर्ड की सुरक्षा और गोपनीयता में सुधार होना चाहिए, साथ ही निजी जानकारी को खतरों और अनधिकृत पहुंच और उपयोग से भी बचाना चाहिए।

जागो हिन्दुओं भय-त्याग आक्रमक बनो...

जिन्ना कौन था जिसने पाकिस्तान बनाया. जिन्ना एक सम्भ्रांत व उच्च हिन्दू परिवार से था. राजा मानसिंह कौन था वो हिन्दू शासक था जिसने अकबर की फ़ौज का सेनापति बन हिन्दुओं का क़त्लेआम व हिन्दू शासकों व राजा रजवाड़ों क़ो मुग़लों के अधीन किया, राजा जयसिंह व जसवंत सिंह कौन थे,वे हिन्दू शासक थे जिन्होंने शिवाजी जैसे हिन्दूहृदय सम्राट व अन्य हिन्दू शासकों पर औरंगजेब की ओर से अत्याचार किये.

हमारे ही देश के वे छप्पन से अधिक देश के सबसे बड़े राजवंश कौन थे, जिन्होंने मुग़लों के साथ पारिवारिक मधुर सम्बन्ध बनाने वास्ते अपनी बहन बेटियों के साथ निकाह कर मुग़ल सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त किया.वे सब हिन्दू ही थे. राणा सांगा इब्राहिम लोदी से लड़ रहे थे तो कई हिन्दू अमात्या लोदी की ओर से लड़ रहे थे और राणा सांगा की ओर से समूची सेना हसन मेवाती के नेतृत्व में लोदी से लड़ रही थी और जब अकबर के लिए हल्दीघाटी में सारे हिन्दू राजाओं के साथ मानसिंह राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे तब शेरशाह सूरी के पोते हाकिम सूरी ही राणा प्रताप की सेना के सेनापति बन राणा की ओर से लड़ते लड़ते प्राण दे दिए मग़र प्रताप के समीप किसी दुशमन को फटकने तक नही दिया.जब एक अकेला महान योद्धा टिपू सुल्तान अंग्रेज़ों की असाधारण सेना व युद्द साधनों से देश की आज़ादी के लिए युद्ध पर युद्ध लड़ रहा था तब सारे ग़द्दार देशी शासक अंग्रेजों के पक्ष में खड़े हों टिपू सुल्तान क़ो हराने के षड्यंत्र में अंग्रेज़ों की लीदें उठाने की दौड़ में लगे

रहे और जब देश की सारी सल्तनो ने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक गुलामी स्वीकार कर ली तो पच्चासी से अधिक उम्र की ज़र ज़र बूढ़ी काया के अन्तिम मुग़ल बादशाह बहादुरशाह ज़फ़र ने अंग्रेज़ों के खलिफ़ हुए 1857 के विद्रोह के संग्राम का नेतृत्व किया जिसमें राणी लक्ष्मी बाईं,तातीयाँ टोपे व फड़नवीस के अलावा सारे हिन्दू शासक अंग्रेज़ों के पक्ष में खड़े रहे. बाबर को लाकर उसका राज स्थापित करने वाला हिन्दू शासक ही था. गजनवी को न्यौता देकर सोमनाथ मंदिर को लूटवाने व लूट की चौथ में हिस्सेदारी का गुनहगार हिन्दू शासक ही था.भगतसिंह क़ो फाँसी जिनके गवाहों पर मिली वे सारे के सारे हिन्दू ही थे. अंग्रेज़ों के खलिफ़ संघर्ष के लिए गाँधी का साथ व गाँधी को सबसे बड़ा चंदा देने वाला मुसलमान ही था. गाँधीजी का प्रारम्भ से अन्त तक कन्धे से कन्धा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला सीमान्त गाँधी मुसलमान ग़फ़्फ़ार खान ही था. आज़ादी की पूरी लड़ाई जिस इंक़लाब के नारे पर टिकी थी उसका जनक मुसलमान था.अंग्रेज़ों से लड़ने वाली आज़ाद हिन्द फ़ौज का कप्तान मुसलमान था.आज़ादी की लड़ाई में फाँसी चढ़ने वाले शहीदों में पच्चतर प्रतिशत मुसलमान थे जिनके नाम दिल्ली के गेट आँफ इण्डिया पर आज भी लिखे हुए हैं. भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरु फाँसी पर चढ़े तो असफाख उल्ला और बिस्मिल खाँ भी फाँसी पर चढ़े.चीन के खलिफ़ मेजर शैतानसिंह ने ज़ो शौर्य व पराक्रम दिखाया उसी तरह हवलदार अब्दुल हामिद ने भी वही करिश्मा दिखाया.देश में सूरदास जैसे महान कवि हुए तो रहीम व रसखान जैसे महानतम कवि भी हुए हैं.देश में होमीजें भाभा व विक्रमसारा भाई जैसे महान वैतनिक हुए वैसे अब्दुल कलाम जैसे विश्व मिसाईल मेन भी पैदा हुए हैं.

आज़ादी से लेकर देश के विकास व नव निर्माण में जितना योगदान,समर्पण व त्याग हिन्दुओं का रहा हैं उतना ही मुसलमानों का भी रहा हैं ,मग़र एक सिहासी जमात सत्ता हड़पने व हथियाने के लिए बेवजह धार्मिक उन्माद का ज़हर फैलाकर आज वो व उसकी समर्थक शक्तियाँ हंगामा व नफ़रतों की ज्वालामुखी भड़का रही हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया,आज़ादी की पीठ में छुरा भौंका,भगतसिंह की फ़ौज को कमजोर करने जिन्होंने भारतीयों की अंग्रेज़ी फ़ौज में बड़ी मात्रा में भर्ती करवाई. देश को विभाजित करने के द्वी राष्ट्र की जिन्ना की चाहत व लक्ष्य को मजबूती दे उसे परवान चढ़ाया.जिनके पार्टी के प्रथम पुरखों ने जिन्ना की मुस्लिम लीग क़ो मजबूत बनाने के लिए साथ मिलकर चुनाव लड़ा और आज के आठ प्रांतो जितने बड़े दो प्रांतों में मिलकर जिन्ना के साथ सरकारें बनाई.इतना ही नही भारत में जिन्ना को गाली देते हैं और इनके एक आका अध्यक्ष पाकिस्तान पहुँच जिन्ना की मज़ार पर माथा टेक उसे महानायक व दूसरे सबसे बड़े इनके नेताओं में सुमार नेता अपनी लिखी पुस्तक में जिन्ना को महान बताते हैं. कोरे दिखावटी अति छद्म राष्ट्रवाद, झूठी देशभक्ति के शगूफ़ों की सड़ीगली नोटंकी के ये दोगले क़िस्म के धोखेबाज़ बहुरूपिये देश में हिन्दू मुस्लिम के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाकर देश को कमजोर, विभाजित व विभाजन का खेल एक विचार धारा की सत्ता व शासन क़ो क़ायम करने के वास्ते उनके द्वारा किया,रचाया व फैलाया जा रहा हैं. देश इन दानवी आत्मघातियों से सावधान नही हुआ तो देश का सत्यानाशा हो जाएगा,बर्बादी में डूब जाएगा. समूचा देश ही नही आने वाली कई कई पीढ़ियाँ तबाह हो जाएगी.

राष्ट्रीय सम्पूर्ण क्रान्ति मंच
गाँधी, डा. लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश धारा का विचार समूह

पुलिस यातायात सुधारे हेलमेट की नौटंकी करे बंद

पेज 1 का शेष

क्या सरकार में, पुलिस स्वास्थ्य विभाग में बैठे हरामखोर जालसाजों को मोटी कमाई के अतिरिक्त कभी दो पहिया वाहन चालक को हेलमेट न पहनने की इन परेशानियों की समझ और उसके कारगर उपाय खोजना ढूंढने व वाहन चालकों को बताने की जरूरत समझ में आती है या केवल केमरे में जिस वाहन चालक नहीं हेलमेट नहीं लगाया है उसको चालान से वसूली करने और जबरदस्ती हेलमेट पहनने के लिए विवश करने में ही आनंद आता है।

दो पहिया वाहन चालक के मस्तिष्क को भारीपन लगने के साथ सिर चटकने लग जाता है। कान को दबे रहने से कान में होने वाली खुजली कान के दर्द और ज्यादा लंबे समय तक दबे रहने से भी दिमाग भारीपन महसूस करने के साथ चटक चलने लगती है। ज्यादा तेज गर्मी होने पर बौखलाहट होने चक्कर आने, जी घबराने मचलाने से उल्टी तक होने लगती है। इससे हेलमेट सुरक्षा की अपेक्षा शरीर को घातक होने के साथ दुर्घटनाओं व बीमारियों को कारण भी बन जाता है। दूसरी तरफ सिर पर भार बने रहने से भारीपन महसूस होने के कारण स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों में दर्द होना, रीढ़ास्थि में दर्द होने जैसी समस्याएं भी खड़ी होने के कारण लंबे समय तक पहनने से लकवा की बीमारी भी हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि हेलमेट वजन में हल्का हो, उसमें बारीक छेद हों ताकि सिर पर पसीना आने और बहने की समस्या को समाप्त किया जा सके और ठंडी हवा लगने से चक्कर आने कानों मैं खुजली चलने व दब जाने के कारण पीछे की आवाज ना सुन पाने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके साथ ही कान के दबे होने से उसमें होने वाली चटकन, पीछे व आजू-बाजू की आवाज न सुनाई पढ़ने से उत्पन्न वह होने वाली दुर्घटनाओं व समस्याओं को रोका जा सके।

कौन वाहन चालक डेढ़ लाख 2 लाख की गाड़ी खरीदने के बाद, सड़कों पर सुरक्षित रहने दुर्घटना की अवस्था में अपने सिर व शरीर का बचाव करने रु.700 का हेलमेट खरीद कर पहनना नहीं चाहता। इसके साथ हीचालकों के माता-पिता, पति-पत्नी, सखा- सहेलियां, मित्र से लेकर आमजन भी चाहता है कि हर दो पहिया वाहन चालक हेलमेट का उपयोग कर न केवल दुर्घटनाओं से वरन साधारण अवस्था में भी धूल धूप धूएं से भी सुरक्षित रहकर, इन सब से होने वाले त्वचा रोगों, धूल उद्योग से होने वाली एलर्जी जो अस्थमा जुखाम खांसी आदि के श्वसन जन्य रोग उत्पन्न करते हैं से भी सुरक्षित रहें। जबकि सर्दी बरसात ऋतुओं में तो यह बहुत ही उपयोगी व सिर को गीला होने से बचाने के साथ वाहन चलाने में भी मुंह, आंख पर सीधे पड़ने वाले बरसात की बूंदों की बौछारों से लगने वाली हल्की चुभन व चोट से अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करता है।

पुलिस केवल वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं पहने हैं वह जिस चौराहे से गुजरेगा उसकी कैमरे में रिकॉर्डिंग कर उसके ऊपर चालान घर पर भेज देगी वह पुलिस के हरामखोर जालसाज आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, सीएसपी से लेकर नीचे यातायात थानों के टीआई, उप निरीक्षक सिपाही से लेकर वसूली करने वाले दल्लों की फौज के साथ यदि वाहन चालक को बिना हेलमेट या अन्य किसी जुर्म में पकड़ने पर यदि उसके पास नगद रोकड़ा नहीं है, तो वह पड़ोस पड़ोस की दुकानों, या खड़े उनके साथी दल्लों व साधारण वस्त्रों में खड़े उनके वसूली बाज एजेंटों के खातों में पैसा डलवा कर वसूल कर लिए जाते हैं। तब वह कैमरे में नहीं दिखता चौराहों पर लगे कैमरे में से निकलने वाले बिना नंबर की गाड़ियों वाले लहराते चलने वाले, कान में इयरफोन लगाकर चलने वाले कार चालक दो पहिया वाहन चालक जो पूरे यातायात को बर्बाद करके आजू-बाजू वाले वाहन चालकों को परेशान करते हैं, सूचीबद्ध गुंडे बदमाश नहीं दिखते बस उन्हें दिखते हैं, तो कैमरे में केवल बिना हेलमेट वाले जिनसे वसूली की जा सके और उनके घर पर चालान भेजकर उनकी समाज में बेइज्जती की जा सके का खेल ही दिखता है। चौराहों पर खड़ी यातायात पुलिस कस्टम यातायात सुधारने वाहन चालकों को समझाइश देने चौराहों पर खड़े होकर पुलिस का सारा स्टाफ कभी यह खोजबीन और अनुसंधान क्यों नहीं करता की आखिरी इस चौराहे पर कितने बजे से कितने बजे तक ज्यादा भीलवाड़ा रहती है परेशानियां होती है जनता को यातायात भारी दबाव रहता है उसको किस प्रकार से सुचारू तरीके से चलने का ख्याल वह अध्ययन करें। थोड़े बहुत हेर फेर करने से आसानी से यातायात के दबाव को कम किया जा सके। वह तो उल्टे ही चौराहों पर खड़े होकर, जंगली हिंसक पशुओं की तरह ताक में खड़ी रहकर वसूली के लिए झपट्टा मारती है। क्योंकि उसके स्थानांतरण पदस्थी में उसने जो मोटा धन दिया है, उसको मासिक कि चुकानी है अपने वरिष्ठों को उसमें से अपना हिस्सा भी बचाना है। उसके लिए उसे मोटी वसूली करनी है यातायात जाए भाड़ में जनता परेशान होती रहे दमदार सक्षम यातायात बिगाड़ते रहें। ज्यादा यातायात के घनत्व वाले व्यावसायिक क्षेत्र में अधिकांश सिर्फ फरवरी करोड़पति अपनी गाड़ियां सड़कों पर खड़े करके यातायात बिगड़ते हैं पर उनकी औकात नहीं होती क्यों? यातायात बाधित करने वाली कारों को आत्यधिक यातायात के दबाव वाले व्यावसायिक स्थलों के रास्तों पर सड़कों पर खड़ी करने वाली करो और गाड़ियों को रोक सके या उनके चालान बना सके क्योंकि उनको उन सब दुकानदारों शॉपिंग मॉल वालों से मोटा महीना मिलता है? इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता की ऐसे वाहन सड़कों पर खड़े कर अन्य वाहन चालकों को, लोगों को परेशान करते रहे, दुर्घटनाओं कारण बनते रहें। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। उनकी बला से।

साप्ताहिक समय माया

डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य नहीं घातक संगठन

विश्व एडस दिवस का सच, कंडोम बेचने का षड़यंत्र

वर्तमान में भारत में प्रतिदिन अनुमानित 15 करोड़ कंडोम उपयोग करते हैं। जिसका रु. 10 के हिसाब से रुपए डेढ़ सौ करोड़ प्रतिदिन में 100 करोड़ विदेश को जाता है। पेशेवर नारियां 2-5 कंडोम अपने साथ रखती हैं। भारत में कंडोम का आयात किया जाता है और यहां की आईटीसी जैसी कंपनियां उसका विपणन करती हैं? बेशक कंडोम में लगाए जाने वाली चिकने अत्यधिक घातक पदार्थ की होती है जो न केवल स्त्रियों को बांझ और पुरुषों को लिंग मुंड पर जलन पैदा करने के साथ बीमारियां भी बांट रही है। वर्तमान में भारत में अनेकों फलों की खुशबू व स्वाद वाले मुखमैथुन के लिए रु 50 से 100 तक में उपलब्ध है। इस क्षेत्र में स्त्रियों के लिए योनि में व पर उपयोग करने वाले फुग्गे भी बाजार में आ चुके हैं। कुल मिलाकर भारत से ही कंडोम की बिक्री से लगभग एक अरब रु हर दिन विदेशी कंपनियां ले जा रही हैं। जो 70-80 के दशक में फैलाए गए एड्स के भय के नाम मोटी कमाई का साधन बन चुका है। हालत यह है, की शादीशुदा युवा जोड़े भी बहुतायत में उपयोग कर स्थाई नपुंसकता और बांझपन का शिकार हो अपना भावी जीवन बर्बाद करने पर तुले हैं। यही कारण है कि छोटे-छोटे शहरों में भी 10-20 परख नली शिशु पैदा करने की दुकानें प्रति जोड़े 5 से 10 लाख वसूल कर चलाई जा रही हैं। अकेले इंदौर

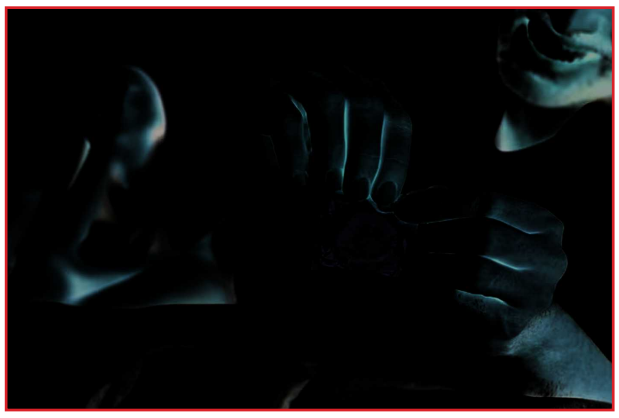

में नपुंसकता व बांझपन की समस्या के कारण, परखनली शिशु पैदा करने, किराए की कोख वह खरीदे हुए वीर्य से बच्चे पैदा करने की दुकानों की संख्या लगभग 300 से ज्यादा हो चुकी है साल भर में अकेले इंदौर में 20 से 25000 से ज्यादा निर्धन स्त्रियां दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने और साल भर में 3 से 5 लाख रुपए कमा रही है जिस पर भारत में कोई सक्षम कानून नहीं पर इसे विश्व घातक संगठन वह उसको धन देने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां को क्या फर्क पड़ता है। उनके लिए तो मानव जीवन को पहले बीमारियां बांटो फिर अपना माल बेचो और अपनी मोटी कमाई करने से मतलब है इसमें भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठे मंत्री से लेकर गांवों में बैठे सरकारी व निजी डॉक्टरो तक को मोटी कमाई करने से मतलब रहता है उनकी बला से देश, पीढ़ी व नस्ल सब बर्बाद हो जाएं। यह केबल डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन उसका परीक्षण करने नई बीमारी पैदा करना फिर अपना हजारों गुना में माल बेंचना। वही हाल उन्होंने अपने कंडोम बेचने के लिए ऐड्स नाम की बीमारी का पूरी दुनिया में हवा फैलाकर 10 पैसे के कंडोम को आसानी से रु. 10 में बेचने का षड्यंत्र था जबकि एडस नाम की कोई बीमारी होती ही नहीं। जो अमेरिका ने अपने देश के बच्चों को 1970-80 में सरकार की तरफ से ध्यान हटाने के लिए और स्कूलों में ही बच्चों को संभोग केली कीड़ा

में रत करने के उपरांत भी बच्चे पैदा ना हो लड़कियां गर्भ की शिकार ना हो। इसलिए उन्होंने पहले फ्री कंडोम बांटने उसका खर्चा निकालने के लिए दुनिया में एड्स की हवा फैलाई गई। ताकि कंडोम बेंच कर मोटा धन बटोरता जा सके।40 साल के बाद आज तक कंडोम का कोई भी वायरसों कीटाणु नहीं खोज पाए। क्योंकि यथार्थ में ऐड्स नाम की कोई बीमारी दुनिया में होती ही नहीं और नहीं अर्थात वास्तविकता यह है यह वर्ल्ड हजाड्र्स ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन और यूरोपियन जालसाज डकैतों की बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों का विश्व घातक स्वास्थ्य बिगाड़ो संगठन एक संयुक्त व्यावसायिक संवर्धन संस्था है। वही कंपनियां इस संगठन को धन देकर अपने हिसाब से चलाती हैं। कोरोना व घातक टीके में इसका सच सामने आ चुका है।

पहले नई खोजों के नाम पहले कुछ भी उल्टा-सीधा बनाओ सिर बीमारियां खड़ी करो और अपना माल बेचो अर्थात उन ने जो बनाया है। उसे खरीदने के लिए पहले भय पैदा करो। फिर अपना माल, दवाइयां, उपकरण जिसमें मधुमेह, हृदय, किडनी, स्वाईन फ्लू, आदि की हजारों गुना दाम पर मोटा कमीशन सरकारों, डाक्टरों को बांट कर बेचों। यह षड्यंत्र 1910 से अमेरिकी और युरोपियन कंपनियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। हर 10 साल में कोई उल्टी-सीधी नई खोज करना फिर डॉक्टर एलोपैथिक के जब बहुत सारी बीमारियां एक दूसरे के विपरीत स्वभाव की मानव शरीर में हो जाने के कारण जब अनियंत्रण की स्थिति बन जाती है। तो आसानी से अपने आप की खाल बचाने के लिए डॉक्टर चला देते हैं कि इसे एड्स हो गया।

मैंने आयुर्वेद और होम्योपैथी का अध्ययन किया और गाहे में बगाहे अभी भी पढ़ता रहता हूं। आयुर्वेद में 14 प्रकार के प्रमेह का वर्णन व उनकी चिकित्सा मिलती है। प्रमेह रोग स्त्री और पुरुषों की यौन और जननांगो रोगों का विवरण देता है।

जिसमें अंतिम उपदंश और सुजाक होते हैं। यदि दोनों एक साथ भी हो जाएं तो भी आयुर्वेद में चिकित्सा के साथ साथ उसके वृहत नियंत्रण के उपाय दिए हुए हैं। जो की महर्षि धन्वंतरि द्वारा हजारों वर्ष पूर्व ही लिख दिए गए थे। उसके बाद में सुश्रुत, चरक आदि अनेकों समय-समय पर जन्में आयुर्वेदाचार्य ऋषि-मुनियों ने भी इन पर काफी काम किया।

पुरुषों स्त्रियों को संभोग के उपरांत जननांगों को सहवास से फैलने वाले रोगों से बचाव के लिए तात्कालिक उपायों में अपने जननांगों को अपने ही मूत्र से प्रक्षालन का सबसे सटीक उपाय दे दिया था। होम्योपैथिक में भी उपदंश व सुजाक के नियंत्रण के लिए जर्मन वैज्ञानिक और होम्योपैथिक चिकित्सा के जन्मदाता हेनमन ने अनेकों औषधियां तैयार कर दी थी। बेशक 16 -17वीं शताब्दी में में मलेच्छ राष्ट्र फ्रांस और यूरोप में उपदंश व सुजाक महामारी का रूप ले लिया था। यथार्थ में लिंग को कवर करने के लिए क्यों बारीक पतले चमड़े का खोल बनाकर संभोग को पूरा करने के लिए कबर तैयार किया गया था ताकि योन रोग ना फैल सके स्त्री और पुरुषों में कंडोम का चलन तभी से शुरू हुआ था।

निसंदेह पूरे आयुर्वेद में लिंग को कवर करके संभोग करने की कोई प्रणाली विकसित नहीं हुई थी। परंतु यौन रोगों से संबंधित, बारीकी से विश्लेषण और चिकित्सा की जितनी व्यवस्था आयुर्वेद में की गई है दुनिया की किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति में आज तक नहीं की जा सकी।

आयुर्वेद में भी प्रमेह की अंतिम दोनों अवस्थाओं उपदंश सुजाक में भी जब अपनी अंतिम अनियंत्रित अवस्था में पहुंचता है तो स्त्री पुरुषों की मृत्यु का कारण बन जाता है जो शरीर के हर अंग में फैल कर भारी विकृतियों उत्पन्न कर देता है।

(शेष पेज 2 पर)

खाद्य एवं औषधि कानून की आड़ में मोटी कमाई करते हैं, निरीक्षक

छोटे निर्माता व विक्रेताओं को खत्म करने का षड्यंत्र

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रखैल विश्व घातक संगठन के इशारे पर नाच, पारंपरिक खाद्यों औषधियों को नष्ट करने पर तुले

भारत में 1965 के बाद अमेरिकी जालसाज षड्यंत्रकारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों व अमेरिकी संयुक्त शैतान संघ या यूएनओ व उसके अनुषांगिक संगठनों के दबाव और मोटा पैसा हजम कर कानून बनाए थोपे गए। जिसमें एक कानून हैजो वास्तविकता खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि.1954 को खत्म कर जिसमें खाद्य वस्तुओं पदार्थों में स्वास्थ्य के लिए घातक अपमिश्रण पाए जाने पर सीधे सजा की व्यवस्था करता था। जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों अमेरिकी वॉलमार्ट युनिलीवर आईटीसी के साथ भारत के टाटा बिरला अंबानी मित्तल व अन्य बड़े खाद्य वस्तु उत्पादकों के लिए काफी कष्टप्रद था। इसलिए अखिलेश अमेरिकी वॉलमार्ट ने जिसे करीबन दुनिया में डेढ़ सौ सरकार खरीद कानून बनवा वहां की आबादी के 30% छोटे उद्योगों व्यवसायों दुकानदारों को खत्म कर अपने शॉपिंग मॉल का मोटा व्यवसाय कर लाखों करोड़ का धन उलीच कर अमेरिका ले जा रही है भारत में भी उसने अटल की सरकार के समय लाखों करोड़ की सौदेबाजी कीऔर सन 2006 में भारत में साड़े 37000 करोड डालर खर्च कर भारतीय रुपए में 33.5 लाख करोड़ और इसका आधे से कम पैसा भारतवके टाटा बिरला अंबानीआईटीसी युनिलीवरव अन्य विदेशी विदेशी कंपनियों ने खर्च कर जिसमें सांसदों को भी 1000 करोड रु उस खाद्य सुरक्षा मानक अधि.06 कानून पर हस्ताक्षर करने का मिला उस समय यह भाजपा राष्ट्र, हिंदुत्व, जिसकी पारंपरिक और सांस्कृतिक वादी पार्टी होने का दम भरने वाली भेड़िया झुंड पार्टी के के सभी सांसद जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी शामिल था और देश के 15 करोड़ से ज्यादा छोटे उद्योगों दुकानों बाजारों मंडियों से लेकर ठेलों व पद मार्गों

पर सब्जी बेचने वालों को खत्म करने का षड्यंत्र करने वाले और जनता की आवाज दबाने वाले उस कानून को देश में लागू करने वाली समिति का अध्यक्ष था। परंतु समय मायाने के श्री अजमेर कोइसी खाद्य मौसी विभाग की कुछ पुराने खाद्य निरीक्षकों द्वारा आग्रह करने और उसका उनकी व्याख्या करने का आग्रह किया और जो उसे कानून के अध्ययन के बाद मैंने उसको पढ़ा और उसके ऊपर लिखा जिससेदेश के बड़े औद्योगिक संगठनों आवाज उठाई तो सरकार ने उस कानून को 5 साल तक लंबित रखा। पर जब अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल लागू करने का आंदोलन किया। 23 जुलाई 2011 को आंदोलन को लंबित कर 16 अगस्त के बाद करने की घोषणा की। देश का सारा मीडिया अन्ना की पूंछ पकड़े नाच रहा था तो 5 अगस्त 2011 से इस कानून को लागू कर दिया गया। बेशक कानून लागू करने में केंद्र सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन और नियंत्रक से लेकर राज्यों के खाद्य औषधि प्रशासन नियंत्रण के हाथ में मोटी कमाई करने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शॉपिंग मॉल बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने उनके खाद्य पदार्थों को मान्यता देने खाद्य पदार्थों की जांच करने, नमूने लेने के नाम पर खाद्य निरीक्षकों से लेकर खाद्य नियंत्रक, स्वास्थ्य मंत्री तक को मोटी कमाई होने लगी।

यही कारण है कि राज्यों के घोर जालसाज डकैत खाद्य एवं औषधि नियंत्रको, स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रधान सचिव से लेकर स्वास्थ्य आयुक्तों तक को मोटा महीना बांट छोटे व्यापारियों औद्योगिक इकाइयों दुकानों बाजारो मंडियों को खत्म करने, मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मोटा धान हजम कर उनकी चाकरी करते हुए मोटे फायदे के लिए सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी और कोरोना के नाम लगभग 15 करोड़ पग मार्गो, ठेले वालों, छोटे दुकानदारों उद्योगों घरेलू इकाइयों बाजारों मंडियों को बर्बाद किया। दूसरी तरफ विभाग में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों सह खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जो पहले से ही शहरी क्षेत्रों में दुकानदारों विक्रेताओं उद्योग लघु खाद्य उत्पादन प्रोसेसिंग व पैकिंग इकाइयों से, मोटा लाखों का धन हजम कर रहे थे। इस कानून के आ जाने से, क्योंकि विदेशी कंपनियां हर कानून अपने व्यवसाय को बढ़ाने प्रतियोगियों को खत्म करने के षड्यंत्रों के अंतर्गत ही सरकारों को खरीद अत्यधिक पेंचीदगियों और उलझन भरे प्रावधानों के साथ बनवा लागू करवाती हैं। जबकि वह षडयंत्रकारी कंपनियां न केवल उन कानूनो का पालन तो दूर खुला उल्लंघन करती हैं क्योंकि वे कानून का पालन करवाने वाले अधिकारियों निरीक्षकों को महीना बांट तन्खैया बना अपनी जेब में लेकर चलती हैं। छोटे-छोटे व्यवसाईयों उद्योगों दुकानों को खत्म करने उनको डराने धमकाने कानूनों में उलझाने 3 साल पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रखैले विश्व घातक संगठन के इशारे पर चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के हर संभागों को वाहन भेजे गए। जिसमें शासकीय गजट नोटिफाई स्थाई सरकारी निरीक्षक अधिकारी कर्मचारी कंडक्टर ड्राइवर तो दूर उस वाहन की भी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। (शेष पेज 5 पर)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803